राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • सोमवार • 16 जून • 2025

www.rashtriyasahara.com

editpagesahara@gmail.com

अनमोल वचन

हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प, किसी भी और संकल्प से महत्त्वपूर्ण है।
-अब्राहम लिंकन

युद्ध की लपटें

इस्राइल के ईरान पर भीषण हमले और ईरान के जवाबी हमले से दुनिया की सांसें अटकी हैं। हालांकि लड़ाई फिलहाल दो देशों तक सीमित दिख रही है लेकिन बड़ा सवाल है कि इस्राइल के हौसले कहां तक बढ़ेंगे। उसने गाजा को मटियामेट कर दिया है। लेबनान और यमन पर जब देखो तब हमले करता रहता है। हिज्बुल्लाह और हूतियों के खिलाफ मोर्चे पहले ही खुले हुए हैं। अब वह ईरान के पीछे पड़ गया है। बहाना ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं दोनों देशों से संयम बरतने की अपील मात्र कर पा रही हैं। इस्राइल को अमेरिका का खुल्लमखुल्ला साथ मिला हुआ है। उसके हमलावर तेवरों और अकड़ से यह बात साफ झलकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ तो ईरान के साथ परमाणु वार्ता कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका उद्देश्य सिर्फ ईरान को दबाना है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वह परमाणु हथियार बनाने की बजाय शांतिपूर्ण उपयोग तक सीमित रहने की संधि करने को तैयार है। इसके बावजूद इस्राइल ने भीषण हमले कर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को भारी क्षति पहुंचाई और कई परमाणु वैज्ञानिकों और जनरलों को मार डाला। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईरान जवाबी हमले भी कर सकता है लेकिन क्षति के बावजूद ईरान ने जवाबी हमले कर इस्राइल को दहला दिया है। अगर दोनों देशों में लड़ाई और फैलती है तो क्या होगा? परिस्थितियां भयावह हालात की ओर संकेत कर रही हैं। इस्राइल को कौन रोकेगा जब ट्रंप उसका साथ देते हुए ईरान को ही सलाहियतें दे रहे हैं। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का रुख गोलमोल है। ले दे कर ईरान के पक्ष में रूस और चीन के ही आने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन रूस पहले ही यूक्रेन के साथ तीन साल से युद्ध में उलझा हुआ है, और फिलहाल उसके इससे बाहर निकलने की सूरत दूर-दूर तक नहीं दिखती। बचा चीन तो वह सबसे पहले अपने व्यापारिक हितों को देखेगा। ट्रंप की चालबाजियों से आजिज ईरान पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल सकता है जैसे कि इराक में स्पेशल फोर्सेज, खाड़ी में सैन्य अड्डे और क्षेत्र में मौजूद राजनयिक मिशनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हमास और हिज्बुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी बलों की ताकत बहुत कुछ कम हो चुकी है, लेकिन वे चुके नहीं हैं। अमेरिका अगर युद्ध में कूदा तो रूस और चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में क्या होगा कोई नहीं जानता।

दक्षिण अफ्रीका की सफलता

दक्षिण अफ्रीका आखिरकार, अपनी आईसीसी ट्रॉफियों से 27 सालों से चली आ रही दूरी को खत्म करने में सफल हो गया। यह दूरी उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर खत्म की है। इस सफलता के साथ ही उनके ऊपर लगा चोकर्स का टेग भी हट गया है। दक्षिण अफ्रीका ने 1998 में एकमात्र आईसीसी ट्रॉफी के रूप में नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी और बाद में इसी ट्रॉफी को चैंपियंस ट्रॉफी का नाम दे दिया गया था। इसके बाद तमाम मौकों पर वह चैंपियन बनने की तरफ बढ़ता दिखा पर महत्त्वपूर्ण मौकों पर लड़खड़ाहट की वजह से उसके साथ चोकर्स का टेग चस्पां हो गया था जो इस सफलता के बाद हट गया है। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के लार्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने उतार-चढ़ाव वाले फाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका की जीत के हीरो एडन मारक्रम और कप्तान टेम्बा बवूमा रहे। मारक्रम ने किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपनी शतकीय पारी से जीत की इबारत लिख दी। कप्तान बवूमा ने अच्छी कप्तानी तो की ही साथ ही हैमस्ट्रिंग का शिकार बनने के बाद भी विकेट पर डटे रहकर मारक्रम का भरपूर साथ दिया। दोनों के बीच 147 रन की साझेदारी जीत का आधार बनी। यह सफलता दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होगी। दक्षिण अफ्रीका ने जब 2023-24 में न्यूजीलैंड का टेस्ट दौरा किया था, तो दौरे में सभी सीनियर खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं कर पाया था। लेकिन इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका ने कम अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताना शुरू किया और इसके बाद टीम ने लगातार आठ टेस्ट जीत कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार खेलने की राह बनाई और वह पहले ही प्रयास में विजेता बन गया। तीन बार इस चैंपियनशिप का अब तक आयोजन हुआ है, और हर बार नई टीम चैंपियन बनी है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन चुकी हैं। भारतीय टीम दो बार फाइनल तक चुनौती पेश करके भी विजेता नहीं बन सकी है। भारतीय टीम इसी माह इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत करके 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत करने जा रही है। इसमें प्रदर्शन से ही इस बार भारत की चुनौती में कितना दम है, पता चल सकेगा।

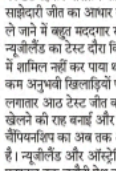

गुरु अर्जुन देव/आर.के. जैन

बलिदान की अमर ज्योति

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं, जो समय की धारा को मोड़ देते हैं-वे न केवल एक व्यक्ति या समुदाय की कहानी कहते हैं, बल्कि मानवता की चेतना को भी नया आयाम देते हैं। 16 जून, 1606 का दिन ऐसा ही एक अनश्वर क्षण रहा, जब सिख धर्म के पंचम गुरु, गुरु अर्जुन देव जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा का ऐसा दीप प्रज्ज्वलित किया जो आज भी अन्याय के अंधेरों को चीरता है। उनका बलिदान केवल सिख इतिहास का एक अध्याय भर नहीं है, बल्कि समूची सभ्यता के लिए एक प्रकाश स्तंभ भी है, जो आज भी हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सहिष्णुता अपनाने और सत्य के लिए जीने की प्रेरणा देता है। गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान एक ऐसी ज्योति है, जो हर उस हृदय में जलती है, जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है।

गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1563 को गोइंदवाल, पंजाब में हुआ। चौथे गुरु गुरु रामदास जी और माता भानी के पुत्र अर्जुन देव बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता के धनी थे। 18 वर्ष की आयु में, 1581 में उन्होंने गुरु गद्दी संभाली और अगले 25 वर्षों तक सिख धर्म को न केवल आध्यात्मिक शक्ति बनाया, बल्कि इसे सामाजिक समानता और मानव कल्याण का प्रतीक भी बनाया। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय ने संगठित रूप लिया और उनके कार्यों ने न केवल सिख धर्म, बल्कि समूचे भारतीय समाज को एक नई दिशा दी।

गुरु अर्जुन देव जी के योगदानों में सबसे उल्लेखनीय है श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की स्थापना। 1588 में शुरू और 1604 में पूर्ण हुआ यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि विश्व में धार्मिक समन्वय और समानता का प्रतीक भी बन गया। उनका दूसरा महान योगदान है 'आदि ग्रंथ' का संकलन, जिसे बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में पूजा गया। 1604 में पूर्ण हुए इस ग्रंथ में गुरु अर्जुन देव जी ने न केवल सिख गुरुओं की वाणी को संकलित किया, बल्कि हिन्दू संतों जैसे कबीर, रविदास, नामदेव और मुस्लिम संतों जैसे बाबा फरीद की रचनाओं को भी शामिल किया। स्वयं गुरु जी ने इसमें 2,218 शबद और श्लोक लिखे, जो भक्ति, प्रेम, और मानवता के उच्च आदर्शों को दर्शाते हैं। 16 जून 1606 को रावी नदी के तट पर स्नान करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अमरता को प्राप्त किया।

बोइंग पर उठते सवाल

सामयिक | विनीत नारायण

अहमदाबाद में हुई भयानक विमान दुर्घटना के बाद भारत सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है, और विमान निर्माण कंपनी बोइंग ने भी सहयोग की पेशकश की है। बोइंग रसूखदार कंपनी है। बावजूद इसके बोइंग की कार्यक्षमता पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फिल्म वायरल हो रही है कि बोइंग कंपनी के ही एक इंजीनियर जॉन बार्नेट, जिन्होंने बोइंग की अंदरूनी क्षमताओं पर महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए थे, 2024 में रहस्यमय परिस्थितियों में बोइंग कंपनी की ही कार पार्किंग में मृत पाए गए थे।

जब किसी विमान दुर्घटना में पायलट भी मारे जाते हैं, तो चलन है कि पावरफुल लॉबी सांठ-गांठ करके जांच का रुख इस तरह मोड़ देती हैं कि दुर्घटना के लिए पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि वो अपना पक्ष रखने के लिए अब जीवित नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जांच एजेंसियां इस दुर्घटना की ईमानदारी से जांच करें। दुनिया भर में लाखों लोग बोइंग कंपनी के विमानों में रोज उड़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के हित में भी यह जरूरी है। बोइंग अपने विरुद्ध अक्सर लगाए जाने वाले आरोपों का स्पष्ट जवाब दे और यदि निर्माण प्रक्रिया में खामियां हैं, तो उन्हें अविलंब सुधारे।

12 जून, 2025 को अहमदाबाद में हुई भयानक विमान दुर्घटना में जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। एयर इंडिया की फ्लाइट 1171 के दुखद हादसे में 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 241 की मौत हो गई और केवल एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे। यह घटना विमान दुर्घटनाओं में एकमात्र बचे लोगों की उन असाधारण कहानियों में से एक है, जो न केवल चमत्कार को दर्शाती हैं, बल्कि मानव की जीवटता और भाग्य की अनिश्चितता को भी उजागर करती हैं। विश्वास कुमार रमेश, 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक हैं, जो भारतीय मूल के हैं। उस दिन सीट नंबर 11ए पर बैठे थे, जो एक आपातकालीन निकास द्वार के पास थी। हादसे के तुरंत बाद विश्वास ने भारतीय मीडिया को बताया, 'मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे बच गया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी मर जाऊंगा लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो खुद को जिंदा पाया।' उन्होंने बताया कि उनकी सीट के पास का हिस्सा जमीन पर गिरा और आपातकालीन निकास द्वार टूट गया था, जिसके कारण वे बाहर निकल पाए।

विमान दुर्घटनाओं में एकमात्र बचे लोगों की कहानियां बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन ये मानव की जीवटता और कभी-कभी भाग्य के खेल को दर्शाती हैं। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें एकमात्र व्यक्ति ही जीवित बचा। जूलियन कोएप्के 17 साल की जर्मन लड़की थीं जो

1971 में पेरू के अमेजन जंगल में लांसा फ्लाइट 508 की दुर्घटना में एकमात्र जीवित बची थीं। विमान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरा और जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई जंगल में जा गिरीं। गंभीर चोटों के बावजूद वह 11 दिनों तक जंगल में भटकती रहीं और अंततः मदद मिलने पर बच गईं। उनकी कहानी साहस और जीवित रहने की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गई। वेस्ना वुलोविच, सर्बियाई फ्लाइट अटेंडेंट थीं जो 1972 में फ्लाइट 367 के मध्य हवा में हुए विस्फोट के बाद एकमात्र जिंदा बची थीं। वह 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद जीवित रहीं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वेस्ना को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन वह ठीक हो गईं और बाद में अपनी कहानी साझा की। चार साल की सेसिलिया सिचन 1987 में नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एकमात्र जिंदा बची थी। यह विमान मिशिगन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 154 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। सेसिलिया को मलबे में दबा हुआ पाया गया और उसकी जान बचाने के लिए व्यापक उपचार किया गया। 12 साल की बाहिया बकारी 2009 में येमेनिया एयरवेज की उड़ान के कोमोरो द्वीप समूह के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिंदा बची थी। वह समुद्र में तैरती रही और बाद में बचाव दल द्वारा बचा ली गई। उसकी कहानी भी दुनिया भर में चर्चा बनी।

विमान दुर्घटनाओं के अलावा, अन्य दुखद हादसों में भी एकमात्र बचे लोगों की कहानियां सामने आई हैं। 1912 में टाइटैनिक के डूबने में कई लोगों की जान गई। लेकिन कुछ लोग, जैसे मिल्विना डीन जो उस समय केवल दो महीने की थी, जीवित बची। वह उन अंतिम लोगों में थी जो इस त्रासदी से बचे थे। 2004 में हिन्द महासागर में सुनामी की प्राकृतिक आपदा में लाखों लोग मारे गए लेकिन कुछ लोग जैसे कि एक इंडोनेशियाई व्यक्ति, जिसे लहरों ने समुद्र में बहा दिया था, चमत्कारिक रूप से बच गया।

विमान दुर्घटना या अन्य त्रासदियों में एकमात्र बचे लोग अक्सर 'सर्वाइवर्स गिल्ट' (जीवित रहने का अपराधबोध) से गुजरते हैं। विश्वास कुमार रमेश ने भी बताया कि वह अपनी जान बचने के बावजूद अपने भाई को खोने के दुख से जूझ रहे हैं। जॉर्ज लैमसन जूनियर, जो 1985 में गैलेक्सी एयरलाइंस की दुर्घटना में एकमात्र बचे थे, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह विश्वास की स्थिति को समझ सकते हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं जीवित बचे लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे लोग अक्सर पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकते हैं। विश्वास के मामले में डॉ. रजनीश पटेल ने बताया कि वह 'पोस्ट-ट्रॉमेटिक अम्नेसिया' से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें दुर्घटना की पूरी तस्वीर याद नहीं है। विश्वास कुमार रमेश का जीवित रहना कई कारकों का परिणाम हो सकता है। प्रो. जॉन हंसमैन, एमआईटी के वैमानिकी विशेषज्ञ, के अनुसार विमान दुर्घटना में जीवित रहने की संभावना सीट की स्थिति, दुर्घटना के प्रकार और त्वरित निर्णय लेने पर निर्भर करती है। विश्वास की सीट आपातकालीन निकास के पास थी, जो बिना किसी बड़े नुकसान के जमीन पर जा गिरी और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला। इसके अलावा, उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और भाग्य ने भी उनकी जान बचाई।

विश्वास कुमार रमेश की कहानी, अन्य एकमात्र बचे लोगों की तरह, हमें जीवन की नाजुकता और चमत्कारों की संभावना की याद दिलाती है। ये कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि विमानन सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती हैं।

(लेख में विचार निजी हैं)

जब किसी विमान दुर्घटना में पायलट भी मारे जाते हैं, तो चलन है कि पावरफुल लॉबी सांठ-गांठ करके जांच का रुख इस तरह मोड़ देती हैं कि दुर्घटना के लिए पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि वो अपना पक्ष रखने के लिए अब जीवित नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जांच एजेंसियां इस दुर्घटना की ईमानदारी से जांच करें। दुनिया भर में लाखों लोग बोइंग कंपनी के विमानों में रोज उड़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा के हित में भी यह बेहद जरूरी है

हाई ब्लड प्रेशर : चमत्कार से कम नहीं जो फल

- 2020 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, रीडिंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, डेविस एंड मार्स की एक संयुक्त रिसर्च के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत पाने के लिए सेब, अंगूर जैसे कई फल काफी मददगार साबित हो सकते हैं
- दो सेब रोज खाना फायदेमंद होता है। अंगूर-एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बीमारी को बढ़ाने वाले सेल्स को रोकने में मदद करते हैं। नींबू-नींबू का रोज सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है संतरा-संतरा में पोटैशियम और कैल्शियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है।
- केला-केले में पोटैशियम ज्यादा और सोडियम कम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पपीता-दो से तीन महीने लगातार खाया जाए तो ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है

(मीडिया इनपुट्स)

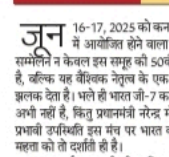

उस पायलट पर उंगली उठाना कितना आसान है, जो अपना पक्ष रखने के लिए अब जीवित नहीं हैं। विमान को बचाने के लिए उनके पास 30 सेकंड की बात कहना कितना आसान है। जिस तत्परता से कुछ टीवी चैनलों ने यह बात कही है, वह बेहद शर्मनाक और दुखद है। किसी की कार्य-निपुणता को अनदेखा करना है। वास्तविक दुनिया में रहिए, टिक टॉक से निकलिए।

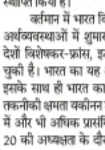

बरखा दत्त, पत्रकार@BDUTT

मोदी की भूमिका है बड़ी

जी-7 शिखर सम्मेलन | डॉ. एस.पी. शाही

जून 16-17, 2025 को कनाडा के कनानास्किस में आयोजित होने वाला 51वां जी-7 शिखर सम्मेलन न केवल इस समूह की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक नेतृत्व के एक नये संतुलन की भी झलक देता है। भले ही भारत जी-7 का औपचारिक सदस्य अभी नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निरंतर और प्रभावी उपस्थिति इस मंच पर भारत की बढ़ती रणनीतिक महत्ता को तो दर्शाती ही है।

इस वर्ष भारत की जी-7 शिखर सम्मेलन में 12वीं सहभागिता होगी जबकि जी-7 शिखर सम्मेलन में यह प्रधानमंत्री मोदी की छठी उपस्थिति है। यह तथ्य स्वयं इस बात का प्रमाण है कि भारत को अब केवल एक आमंत्रित देश के रूप में ही नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श में एक सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की जी-7 शिखर सम्मेलन में निरंतर सहभागिता ने भारत की भूमिका को केवल आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि स्वयं को एक वैश्विक नीति-निर्माता के रूप में भी स्थापित किया है।

वर्तमान में भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, जिसकी जीडीपी कई जी-7 देशों विशेषकर-फ्रांस, इटली और कनाडा-से अधिक हो चुकी है। भारत का यह आर्थिक प्रभाव ध्यान खींचता है। इसके साथ ही भारत का युवा जनसांख्यिकीय लाभ और तकनीकी क्षमता यकीनन उसे एक वैश्विक साझेदार के रूप में और भी अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। वर्ष 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को प्रभावशाली ढंग से विश्व मंचों पर प्रस्तुत किया था जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति और भी सुदृढ़ हुई है।

भारत का जी-7 शिखर सम्मेलन में दृष्टिकोण बहुआयामी रहा है। इसलिए कि वह इस मंच को केवल आर्थिक नीति निर्धारण का अवसर भर नहीं मानता, बल्कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर साझा रणनीति तैयार करने के लिए एक अवसर के रूप में भी

G7 Summit 2025 – Kananaskis, AB

देखता है। इस वर्ष के जी-7 एजेंडे के तीन प्रमुख स्तंभ हैं- 1. शांति और सुरक्षा की रक्षा, 2. ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन, और 3. भविष्य के लिए साझेदारी। इन सभी में भारत की नीति और प्राथमिकताएं प्रतिध्वनित होती हैं। कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई), खनिज सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत का योगदान इस कदर रहा है कि भारत आज विश्व में एआई के अनुसंधान एवं विकास में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान, भारत स्टैक जैसे नवाचारों ने भारत को टेक्नोलॉजिकल सुपरपावर के रूप में उभारा है। जी-7 में यह अनुभव साझेदारी के रूप में काम आ सकता है, विशेषकर विकासशील देशों की डिजिटल समावेशिता में।

भारत लगातार इस बात पर बल देता आया है कि वैश्विक निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 जैसे मंचों पर बार-बार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की समस्याएं भी वैश्विक एजेंडे का हिस्सा बनें। प्रधानमंत्री मोदी की जी-7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के साथ कई द्विपक्षीय वार्ता बैठकें भी प्रस्तावित हैं। ये वार्ताएं भारत की रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने का अवसर देंगी, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में संयुक्त निवेश, आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में।

जी-7 शिखर सम्मेलन अब केवल एक पश्चिमी देशों का क्लब भर नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन चुका है जहां वैश्विक नेतृत्व की नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भागीदारी इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल एक श्रोता या दर्शक भर नहीं रहा, बल्कि वह एक निर्णायक आवाज भी बन चुका है। भारत का दृष्टिकोण वैश्विक समरसता, साझा विकास और समावेशी भविष्य की ओर केंद्रित है, और जी-7 जैसे मंच भारत को इसी वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। कहा जा सकता है कि भारत की भागीदारी, केवल उपस्थिति नहीं दर्ज कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अपना एक अलग प्रभाव है।

(लेखक मगध विवि के कुलपति हैं। लेख में विचार निजी हैं)

प्राथमिकता | श्रीराम शर्मा आचार्य

पड़ोस में आग लगने पर भोजन पकाने जैसा आवश्यक काम भी पीछे कभी के लिए छोड़ना पड़ता है। कितने ही काम सामने हों तो भी उनमें बुद्धिमानी का कदम यह होता है कि प्राथमिकता देने और पीछे धकेलने की एक सुव्यवस्थित शृंखला बनाई जाए। इस क्रम को बिगाड़ देने पर पूरा परिश्रम करने पर भी बात बनती नहीं और समस्याएं सुलझने के स्थान पर और भी अधिक उलझ जाती हैं। इन दिनों प्रत्येक विज्ञजन के लिए करने योग्य सामयिक कार्य एक ही है, कि लोक मानस के परिष्कार का महत्त्व समझा जाए और आस्था संकट का निवारण करने के लिए प्राणप्रण से जुट पड़ा जाए। इस एक ही व्यवधान के समाधान पर समय की समस्त गुत्थियों का सुलझ सकना निर्भर है। यह सब अनायास ही संभव नहीं हो सकता। इस श्रेय पथ पर चल सकना मात्र उन्हीं के लिए संभव है, जो अपनी आकांक्षा-उत्कंठा को तृष्णा से हटाएं और उसे उतनी ही भावनापूर्वक श्रेय साधना के लिए लगाएं। यह आंतरिक परिवर्तन ही बाह्य क्षेत्र में वह सुविधा उत्पन्न कर सकता है, जिसके सहारे शरीर निर्वाह की तरह ही आत्म-कल्याण और विश्व-कल्याण का महान प्रयोजन बिना किसी के, नितांत सरलतापूर्वक सधता रहे। परमार्थ परायणों में से एक भी भूखा, नंगा नहीं रहा। उनके पारिवारिक उत्तरदायित्वों में से एक भीरुका नहीं पड़ा रहा। तरीके अनेकानेक हैं। अपना सोचा तरीका ही एकमात्र मार्ग नहीं है। नये सिरे से नये उपाय सोचने पर ऐसे समाधान हर किसी को उपलब्ध हो सकते हैं, जिनसे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। निर्वाह किसी के लिए समस्या नहीं। कठिनाई यही है- अनंत वैभव की लिप्सा और कुटुम्बियों को सुविधा संपदा से लाद देने की लालसा। यदि परिवार के सदस्यों को श्रमजीवी, स्वावलंबी बनाने की बात सोची जाए, औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार किया जाए तो इतने भर से जीवन को सार्थक बनाने वाली राह मिल सकती है। प्रश्न यही है कि शरीर के लिए जिया जाए या आत्मा के लिए। दोनों में से एक को प्रधान, एक को गौण मानना पड़ेगा। यदि आत्मा की वरिष्ठता स्वीकार की जा सके तो उन प्रयोजनों को पूरा करना पड़ेगा जिनके लिए सृष्टा ने यह दुर्लभ अवसर उच्चस्तरीय उपयोग के निमित्त प्रदान किया है।

रीडर्स मेल

इस्राइल-ईरान युद्ध के खतरे

इस्राइल और ईरान में युद्ध विश्व शांति के लिए खतरा है। इसलिए विश्व समुदाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को समाप्त करने की पहल करे। दोनों देशों में उत्तेजना और आक्रोश से लगता है कि पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध होने वाला है जिसकी चपेट में पूरा विश्व आ सकता है। यूक्रेन-रूस, इस्राइल-फिलिस्तीन और इस्राइल-ईरान के बीच युद्ध रोकने के गंभीर प्रयास होने चाहिए। इनमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन और इस्राइल में बड़ी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ है लेकिन इस्राइल अपनी जिद पर अड़ा रहा है और विश्व समुदाय इस्राइल पर दबाव बनाने में असमर्थ रहा है। इस्राइल के प्रधानमंत्री यह कहना उचित नहीं है कि यदि ईरान बदला लेता है, तो ईरान को खत्म करने की योजना बनाएंगे और जला देंगे। इस्राइल के दो बार के हमलों में अब तक ईरान के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, इस पर विश्व समुदाय को सोचना होगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

असहनीय त्रासदी के सबक

12 जून, 2025 को देश ने एक भीषण दुर्घटना देखी। लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान 1171, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद रिहायशी इलाके में एक हॉस्टल से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान 500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया था जब मेडे कॉल किया गया। ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षण में पायलट की तत्काल कार्रवाई और शांत निर्णय उसके प्रशिक्षण और साहस का प्रमाण है। 'पावर ऑन स्टॉल' उड़ान के दौरान अपर्याप्त लिफ्ट के कारण विमान नीचे उतरता है। हालांकि, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) का विश्लेषण पूरा होने तक कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त विमान के एफडीआर और सीवीआर (ब्लैक बॉक्स) बरामद कर लिए गए हैं। इनको विमान जांच ब्यूरो-एआईबी-द्वारा डिकोड किया जाएगा। यह समय विमानन में सुरक्षा, प्रशिक्षण और पारदर्शिता के मानकों को और मजबूत करने का है। गलतियों से सीखना, सच्चाई को समझना और उड़ान भरने के लिए आवश्यक विश्वास को फिर से बनाना, इस त्रासदी से मिल सकने वाला सबक है, लेकिन इस समय इस दर्द को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं, यह सच है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

डिजिटल क्रांति का अजीब दौर

आज हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा है-देह प्रदर्शन का। कहीं चटखती-फड़कती रील्स में, कहीं भड़काऊ-उलझाऊ डांस मूव्स में और कहीं जूम इन होती नजरों के बीच, बस एक ही प्रदर्शन, अपनी चपल देह की अदा का। मानो यही सब देह ही पहचान बन गई हो। सच कहा जाए तो इस दौर में देह का कारोबार जितना खुल कर हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। सोशल मीडिया ने देह को 'प्रॉडक्ट' बना दिया है, जिसे जितना ज्यादा दिखाओ, उतना ज्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज बटोर लो। मानो आत्मसम्मान का कद अब कमेंट्स की लंबाई और लाइक्स की संख्या से मापा जाने लगा हो। वह नारी जो कभी सभ्यता की पहचान थी, अब डिजिटल बाजार में बिक रही है। यह डिजिटल क्रांति का अजीब दौर है, जहां औरतें 'बोल्ड' होने का झूठा अर्थ 'बदन दिखाने' से जोड़ बैठी हैं। क्या यह प्रगतिशीलता है?

मनोज श्रीवास्तव, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

वर्ष-34, अंक 300

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बाराखंभा रोड, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

कूटनीति किसी को ठेस पहुंचाए बिना साफ-साफ सच कहने की कला है। -विंस्टन चर्चिल

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड क्षेत्र में हुई हेलिकॉप्टर दुर्घटना सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, भविष्य में ऐसे हादसे न हों, इसके लिए सख्त सुरक्षा मानदंड भी अपनाए जाएं।

सुरक्षा पर सवाल

अहमदाबाद में बृहस्पतिवार को एयर इंडिया के विमान क्रैश के दो दिनों बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान रविवार सुबह गौरीकुंड क्षेत्र में केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी आ रहे हेलिकॉप्टर के क्रैश होने की दर्दनाक घटना में 23 महीने के बच्चे समेत सभी सात लोगों की मौत न केवल मानवीय त्रासदी है, बल्कि सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इससे पहले बीते छह हफ्तों में उत्तराखंड में इसी रूट पर हेलिकॉप्टर की तीन बार इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है और दो बार हेलिकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जो हेलिकॉप्टर सेवा संचालन में गंभीर लापरवाही का संकेत देते हैं। इस हादसे के लिए प्रारंभिक कारण खराब मौसम को बताया जा रहा है, लेकिन उड़ान से पहले मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए था। चारधाम यात्रा मार्ग की कठिन भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हेलिकॉप्टर सेवा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार श्रद्धालुओं के लिए वरदान है, लेकिन सुरक्षा में लापरवाही इसे खतरनाक बना देती है। ऐसे में उचित ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐसे हादसों को गंभीरता से लेते हुए हेलिकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए एक समिति गठित कर सख्त एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की समिति हेलिकॉप्टर संचालन के सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एसओपी तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इनका संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। चारधाम यात्रा के सीजन में हेलिकॉप्टर सेवाओं की मांग बढ़ने से अनियमितता भी बढ़ जाती है। हेलिकॉप्टर सेवाओं को संचालित करने वाली निजी कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती हैं और यात्रियों की सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता व्यावसायिक लाभ को देती हैं। राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्वतीय

इलाकों में हेलिकॉप्टर सेवाओं को स्पष्ट, सख्त और अद्यतन गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक उड़ान से पहले मौसम पूर्वानुमान और तकनीकी निरीक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके दुखों की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, भविष्य में ऐसे हादसे न हों, इसके लिए सख्त सुरक्षा मानदंड भी अपनाए जाएं।

विश्व जनमत से हमारी मुलाकात

छद्म नैरेटिव युद्धों के दौर में जब पाकिस्तानी दुष्प्रचार मशीन अपने काम में लगी है, तब हमने अपना कर्तव्य समझा कि हम पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई को विश्व जनमत के सामने रखें। हमारे प्रतिनिधिमंडलों की सफलता उन्हें मिले समर्थन और सम्मान से ही जाहिर होती है।

सूचना युद्ध के इस दौर में हमने अपना कर्तव्य समझा कि हम पूरी दुनिया को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा की गई भयानक और बर्बर हत्याओं की सच्चाई और वास्तविकताओं से अवगत कराएं। इसी के अनुरूप भारत सरकार ने भाजपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम, डीएमके, बीजेडी, शिवसेना और अन्य दलों के 59 सांसदों वाले सात सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजने का फैसला किया। प्रतिनिधिमंडल ने 32 देशों की यात्रा की, जिसमें विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं, मीडिया, थिंक टैंक और प्रवासी भारतीयों के साथ बैठकें और रणनीतिक बैठकें कीं।

यह बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत के रुख को एक स्वर में प्रस्तुत करने के लिए राज्य के नेताओं के साथ सम्मेलन आयोजित करने का पहला उदाहरण था। इसमें पांच धर्मों (हिंदू, सिख, बौद्ध, मुस्लिम व ईसाई) के सदस्य शामिल थे, जिन्होंने राज्य प्रायोजित अपराधों के खिलाफ भारत के स्वयं के बचाव के अधिकार की वकालत की। वाशिंगटन डीसी में प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद का मुकाबला करने और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ व्यापक चर्चा की। ब्रुसेल्स में, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के समूह ने बेल्जियम के चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष पीटर डी रूवर से मुलाकात की, जिन्होंने भारत के साथ मजबूत एकजुटता व्यक्त की।

डॉ. निशिकांत दुबे
सांसद एवं अध्यक्ष, संचार एवं आईटी समिति

कुवैत में, हमारे मिशन ने एक 'दीवानिया' या अनौपचारिक बातचीत का आयोजन किया था, जहां प्रतिनिधिमंडल को पूर्व उप प्रधानमंत्री, चार पूर्व मंत्रियों, खाड़ी सहयोग परिषद के पूर्व महासचिव और कुवैत के तीन प्रमुख समाचार पत्रों के वरिष्ठ संपादकों सहित 40 से अधिक शीर्ष कुवैतियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनका आतिथ्य पश्चिम एशिया में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को मान्यता देता है, जिसमें हमारे पड़ोसी द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के शिकार के रूप में भारत की स्थिति के लिए बढ़ता समर्थन भी शामिल है।

अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने ब्राजील में सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर नेल्सिन्हो ट्रैड से मुलाकात की। ब्रिटेन में टीम ने कंजर्वेटिव पार्टी के सह-अध्यक्ष लैस्टन के लॉर्ड डोमिनिक जॉनसन और अन्य वरिष्ठ सांसदों के साथ मुलाकात की। स्पेन, मलयेशिया, लाइबेरिया और अन्य देशों के नेताओं के साथ इन उच्चस्तरीय बातचीत ने भारत की कूटनीतिक भागीदारी की व्यापकता और आतंकवाद के खिलाफ इसके दृढ़ रुख के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन को प्रदर्शित किया। पश्चिम एशियाई देशों-सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन व अल्जीरिया-ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उदार राजनयिक शिष्टाचार प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल को चार आधिकारिक लंच और डिनर की मेजबानी दी गई, जो न केवल प्रोटोकॉल का संकेत था, बल्कि भारत के प्रति क्षेत्र के गहरे सम्मान और हमारे संदेश को जिस गंभीरता से प्राप्त किया गया, उसका प्रदर्शन भी था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर स्थानीय अधिकारियों ने भारत और कुवैत के बीच व्यापार व मौद्रिक संबंधों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। बहुत कम लोगों को याद होगा कि 1947 से 1962 तक कुवैत और बहरीन में भारतीय रुपया वैध मुद्रा के रूप में काम करता था। यह हमारे देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक था। इस प्रयास को मीडिया व कूटनीतिक हलकों ने सराहा और भारत को एक स्थिर व विश्वसनीय शक्ति के रूप में दर्शाया गया। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की अपनी यात्रा के दौरान, हम वास्तविक सच्चाई को प्रस्तुत कर पाए कि यह दो देशों के बीच संघर्ष नहीं है, बल्कि आतंकवाद की आड़ में काम कर रहे पाकिस्तानी सेना के तत्वों द्वारा भारतीय लोगों पर सीधा हमला है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय नेताओं के बीच तत्काल स्वीकृति और प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। कुवैत पर इराकी आक्रमण या यमन में हूतियों द्वारा सऊदी अरब में उग्रवाद की धमकियों जैसे संघर्ष और उग्रवाद के पीड़ितों के कड़वे अनुभव के साथ, ये देश, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं।

कुवैत और सऊदी अरब में बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने याद दिलाया कि कैसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2009 में शर्म अल-शेख में अपने पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात की और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद के परस्पर पीड़ित के रूप में बताया गया-बिना आईएसआई या पाकिस्तानी सेना का नाम लिए। प्रतिनिधिमंडल ने यह स्पष्ट किया कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद के सामने समझौतापूर्ण कूटनीति केवल हमलावर को बढ़ावा देती है। हमारे सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने समझाया कि कैसे पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख और पूर्व आईएसआई प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस आतंकवादी नेटवर्क की प्रतीकात्मक कड़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के 2018 से 2022 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने और फिर भी विदेशी सहायता प्राप्त करने पर सवाल उठाया। पाकिस्तान अपनी गरीबी को कम करने के लिए मिलने वाली अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय सहायता को व्यवस्थित रूप से प्रॉक्सी समूहों को प्रायोजित करने और भारत विरोधी आतंकी ढांचे को मजबूत करने में लगा रहा है।

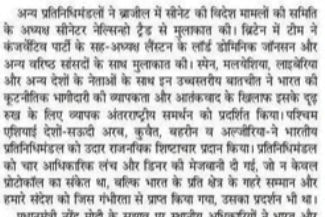

हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यह गलतफहमी दूर की कि सिर्फ मुस्लिम बहुल देश ही फलस्तीनियों को लेकर चिंतित हैं। हमने बताया कि भारत हमेशा से दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है, जिससे इस्राइल और फलस्तीन, दोनों को सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य मिल सके। साथ ही, हमने बताया कि आज फलस्तीनियों की दुर्दशा दुखद रूप से हमास से जुड़ी हुई है, जो एक आतंकवादी संगठन है, जिसने गाजा में शासन पर कब्जा कर लिया है।

यह देखकर हर्ष हुआ कि हमारे सऊदी समकक्षों ने भारत के दृष्टिकोण के साथ उल्लेखनीय सामंजस्य दिखाया। जब पहलगाम में हमला हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे और प्रतिनिधिमंडल को लगा कि वे उनके द्वारा शुरू की गई कूटनीतिक गति को आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी थिंक टैंकों ने पहलगाम हमले को केवल आतंकवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना व आईएसआई द्वारा समर्थित एक संगठित सैन्य ऑपरेशन के रूप में परिभाषित किया, इसे 'राज्य समर्थित विषम युद्ध' कहा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 32 देशों में सात बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों ने दिखाया कि एकता हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने एक शक्तिशाली संदेश दिया : भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सैन्य और कूटनीतिक रूप से कार्रवाई कर सकता है और करेगा। (साथ में हर्षवर्धन शृंगला, आईएफएस एवं पूर्व विदेश सचिव)

edit@amarujala.com

जीवन धारा

हेनरी डी. थोरो

हमारे हर कदम पर जटिलता हमें बांध लेती है। अनगिनत इच्छाएं व व्याकुलताएं हमें भटकाती हैं और हमारा जीवन छोटी-छोटी बातों में बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें हर छोटे पल को पूर्ण रूप से जीना चाहिए।

ताकि अंत में पछताना न पड़े

मैंने प्रकृति का हाथ थामा और वन में गया, क्योंकि मैं जीना चाहता था। मैं जीवन के आवश्यक सत्य को सामने लाना चाहता था और देखना चाहता था कि यह मुझे क्या सिखा सकता है, ताकि मरते वक्त पछताना न पड़े कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। मेरे लिए जीना बहुत प्रिय है। हमारे लिए जो सच में मायने रखता है, शांत चिंतन, प्रकृति की लय, सत्य की खोज, यही जीवन है। हमारे जीवन में खुशी केवल चीजों का संग्रह करने में नहीं, बल्कि आवश्यक चीजों को पहचानने में है। जीवन का मतलब है, हर कदम सोच-समझकर उठाना और समय के साथ उसका मूल्य तौलना। हमारे प्रत्येक कदम पर जटिलता हमें बांध लेती है। अनगिनत इच्छाएं और व्याकुलताएं हमें भटकाती हैं। इस तरह हमारा जीवन छोटी-छोटी बातों में बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें हर छोटे पल को पूर्ण रूप से जीना चाहिए। जीवन अनेक 'छोटे क्षणों' का संग्रह है और प्रत्येक क्षण में अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। हर पल को थाम लें और दुनिया से पूरी तरह जुड़ जाएं। चाहे पौधे उगाना हो या चींटियों को देखना, हर चीज में अनोखा आनंद है। यह सजगता हमें वर्तमान में ले आती है।

इस धरती पर जीवन जीना मुश्किल नहीं, बल्कि एक खेल है, अगर हम सरलता और बुद्धिमानी से जिएं। ज्यादातर लोग निराशा का जीवन जीते हैं। इससे बचने के लिए, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, सच्चे मन से जीना होगा। एक हल्की-सी बारिश घास पर जमी धूल को साफ कर उसे हरा कर देती है। इसी तरह बेहतर विचारों के आने से हमारी संभावनाएं उज्ज्वल हो जाती हैं। यदि हम हमेशा वर्तमान में जिएं और प्रत्येक बदलाव का लाभ उठाएं, जैसे घास हल्की ओस के प्रभाव को स्वीकार करती है, तो जीवन का असली आनंद उठा सकेंगे। जीवन में प्रकृति खुशी की राह का केंद्र है। पत्तियों की सरसराहट, नदी की लहरें, ये केवल दृश्य नहीं, बल्कि सार्थक जीवन के साथी हैं। प्रत्येक मौसम को जिएं। प्रकृति की गोद में हमें शांति और ऊर्जा, दोनों मिलती हैं। हमारा जीवन नदी के पानी की तरह है, जो लगातार बहता रहता है, बदलता रहता है, और गति से भरा रहता है। जिस तरह नदी का पानी ऊंचा-नीचा या शांत-अशांत हो सकता है, उसी तरह जीवन में हमारे अनुभव और भावनाएं भी हो सकती हैं। यदि कोई अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़े और वह जीवन जिए, जिसकी उसने कल्पना की, तो उसे ऐसी सफलता मिलेगी, जो सामान्य घड़ी में नहीं मिलती। सच्चे सपनों का पीछा करें। सरलता, सजगता, और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जिएं। जीवन जीने का कोई खास समय नहीं होता, इसलिए हर पल खुश रहें। खुशी मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना अधिक आप इसका पीछा करेंगे, उतना ही यह आपसे दूर भागेगी, लेकिन यदि आप अपने आसपास की अन्य चीजों पर ध्यान देंगे, तो यह धीरे से आकर आपके कंधे पर बैठ जाएगी।

खुद को गंभीरता से लें

सूत्र

हमारा स्वयं को देखने का नजरिया मायने रखता है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही अहम होता है। यदि आप खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो बहुत जल्द आप अपने रोजमर्रा के जीवन में हंसी के पात्र बन जाएंगे। हर पल अपने विचार को बेहतर करें और जीवन को सुंदर बनाएं।

दूसरा पहलू

मुगल शासक शाहजहां ने बाइबिल में वर्णित किंग सोलोमन के सिंहासन की तरह अपने लिए राजसिंहासन बनवाया था।

ताजमहल से भी कीमती था शाहजहां का तख्त-ए-ताउस

इतिहास के धुंधले गलियारों में बसी कुछ दास्तानें अधूरी-सी रह जाती हैं। कभी सारी दुनिया को चकाचौंध करने वाले तख्त-ए-ताउस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुगल शासक शाहजहां ऐसा सिंहासन बनवाना चाहता था, जो किंग सोलोमन के जैसा हो। बाइबिल में सोलोमन के सिंहासन के वैभव का बखान है। शाहजहां ने वैसा ही सिंहासन बनवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। तख्त-ए-ताउस या मयूर सिंहासन को बनाने में ताजमहल से दोगुना यानी 1,150 किलो सोना और 230 किलो रत्नों का इस्तेमाल किया गया। सिंहासन में बने दो मोरों की पूंछ भी सोने से बनी थी। मुगल इतिहासकार इनायत खान के अनुसार, इसे तब 2.14 करोड़ रुपये की लागत से बनवाया गया था।

भूपेंद्र कुमार

तख्त-ए-ताउस को बनाने में 1,150 किलो सोना और 230 किलो रत्नों का इस्तेमाल हुआ था, जिनकी कीमत तब करीब 2.14 करोड़ रुपये थी।

17वीं सदी में आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि सिंहासन सोने के छह विशाल पायों पर टिका था। टैवर्नियर ने लिखा है, इसकी छतरी को बेशकीमती रत्नों से सजाया गया था। शाही इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है कि यह शासन की भव्यता का प्रतिबिंब था, जो 3.5 गज लंबा, दो गज चौड़ा और पांच गज ऊंचा था। अरबी और फारसी में मोर को ताउस कहते हैं, तभी इसे तख्त-ए-ताउस कहा गया। इसका वजन 31 मन 20 सेर था। हजारों कारीगरों ने इसे सात साल में तैयार किया। पहले यह आगरा किले के दीवाने आम में रहा, लेकिन जब राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई, तो इसे लाल किले के दीवाने खास में रखा गया। शाहजहां इसी पर बैठकर शाही फैसले सुनाता था, पर 1658 में शाहजहां को बेटे औरंगजेब ने आगरा किले में कैद कर लिया और वहीं उसकी मौत हुई। वर्ष 1739 में फारस के लुटेरे नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और तख्त-ए-ताउस भी अपने साथ ले गया। 1747 में नादिर शाह की उसके अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद खजाने की लूट शुरू हो गई। उसी दौरान इसे तोड़ दिया गया और इसके कीमती हिस्से दुनिया भर में बिखर गए। ईरान पर 1794-1925 तक राज करने वाले कजर वंश के शाही सिंहासन के पाये तख्त-ए-ताउस के ही बताए जाते हैं। इसका एक हिस्सा तुर्किये के तोपकापी पैलेस में है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम में तख्त-ए-ताउस का एक पाया बताया जाता है, एक हिस्सा लंदन के एल्बर्ट म्यूजियम में है, पर पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। तख्त-ए-ताउस को ऊंचे चबूतरे पर रखा गया, ताकि ईश्वरीय कृपा रहे। ...पर शाहजहां और तख्त-ए-ताउस, दोनों का ही अंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तख्त-ए-ताउस कहां गया, किसी को ठीक से नहीं पता, और शाहजहां ने अपने आखिरी वर्ष जेल में काटे। यही तो इतिहास की विडंबना है।

आंकड़े

समुद्री प्रदूषण

दुनिया भर के महासागरों में होने वाले प्रदूषण के सबसे बड़े कारकों में प्लास्टिक और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।

प्लास्टिक बैग	14.1%
प्लास्टिक बोतल	11.9%
खाद्य कंटेनर	9.4%
रैपर	9.1%
सिंथेटिक रोप	7.9%

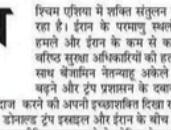

आंकड़े समुद्री प्रदूषकों के, प्रतिशत में | स्रोत : Statista

भक्त श्रीरामकृष्ण जी को स्वप्न में एक महात्मा ने पानी में डूबने से बचाया। सुबह वह उनको ढूंढने निकले, तो मेवाड़ में वही संत उन्हें मिल गए।

ईश्वर कृपा से ही मिलती है भक्ति

अंतर्यात्रा
संकलित

भक्त श्रीरामकृष्ण का जन्म सोढ़ा नामक ग्राम में हुआ था। वह इकतीस वर्ष के हुए, तो एक रात सोते समय उनके चरणों पर वज्र का चिह्न देखकर एक ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि यह तो कोई संत हैं। अब तक गुप्त क्यों हैं? हो सकता है, भगवान की ऐसी ही इच्छा हो। उसी दौरान सोते समय श्रीरामकृष्ण जी को स्वप्न आया कि वह नदी में बहते जा रहे हैं, पानी की धारा इतनी तेज है कि उनका बचना मुश्किल लग रहा है। तभी एक सिद्ध महात्मा आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें पानी की धारा से किनारे पर लाकर उनकी जान बचाते हैं।

नींद खुलने पर श्रीरामकृष्ण जी के अंदर चेतना जागृत हो गई और वह स्वप्न में दिखे उन महात्मा को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में उनके मन में वैराग्य के गहरे विचार आने लगे। जैसे-जैसे वह आगे बढ़े ईश्वरीय कृपा से संसार के दुख और अनित्यता की छाप उनके हृदय पर गहरी होती गई। जब श्रीरामकृष्ण जी मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम पहुंचे, तो वहां उन्हें वही महात्मा मिले, जिन्होंने उन्हें स्वप्न में नदी की तेज धारा में बहने से बचाया था। उन्होंने श्रीरामकृष्ण जी को योग्य शिष्य समझकर भगवत तत्व का उपदेश दिया और उनका नाम श्रीरामचरण जी रख दिया। श्रीरामचरण जी लोगों से कहते थे कि ईश्वर भक्ति भगवान की कृपा से ही मिलती है। वह लोगों को राम नाम के महामंत्र का उपदेश देते थे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 20 अगस्त, 1953

गोदावरी की बाढ़ से पचास करोड़ की भारी क्षति

गोदावरी की बाढ़ से पचास करोड़ की भारी क्षति

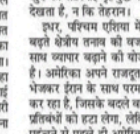

गैर-सरकारी सूत्रों का कथन है कि गोदावरी की बाढ़ की वजह से पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में पचास करोड़ रुपये से भी अधिक के संसाधनों की क्षति का अनुमान है और दस लाख से भी अधिक लोग बेघर हो गए हैं।

पश्चिम एशिया में बदलता शक्ति संतुलन

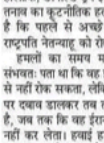

ईरान से चल रही अमेरिका की परमाणु वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही इस्राइल का हमला पश्चिम एशिया में नए शक्ति संतुलन का संकेत है।

नताशा लिंडस्टेड

अंतरराष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले और ईरान के कम से कम दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की हत्या के साथ बेंजामिन नेतन्याहू अकेले आगे बढ़ने और ट्रंप प्रशासन के दबाव को नजर अंदाज करने की अपनी इच्छाशक्ति दिखा रहे हैं। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का कूटनीतिक हल चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से अच्छे संबंधों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति नेतन्याहू को रोकने में असमर्थ थे।

हमलों का समय महत्वपूर्ण है। ट्रंप प्रशासन को संभवतः पता था कि वह इस्राइल को ईरान पर हमले करने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसने सोचा कि वह इस्राइल पर दबाव डालकर तब तक हमला करने से रोक सकता है, जब तक कि वह ईरान के साथ नया परमाणु समझौता नहीं कर लेता। हवाई हमले से कुछ घंटों पहले ट्रंप ने कहा था, 'मुझे लगता है कि ईरान के साथ कोई समझौता हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई व्यवधान आए।'

अमेरिका का इस्राइल पर कितना असर है, इसको लेकर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। जो बाइडन प्रशासन द्वारा महीनों तक की गई तैयारी के बाद ट्रंप जनवरी में इस्राइल और हमास में संघर्ष विराम कराने में सफल रहे। लेकिन वार्ता के एक हिस्से के रूप में नेतन्याहू वेस्ट बैंक में बसने वालों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में सफल रहे, जिससे उन्हें वहां कार्य करने की पूरी छूट मिल गई। इसके अलावा, अमेरिका ने इस्राइल को 2,000 पाउंड के बमों के हस्तांतरण पर लगी अपनी रोक भी हटा दी, जो इस्राइल के लिए एक और रियायत थी।

अमेरिका गाजा में मानवीय संकट को रोकने में भी अक्षम साबित हुआ। वाशिंगटन इस्राइल द्वारा लेबनान पर हमले और ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला को खत्म करने के उसके प्रयासों को रोकने में भी शक्तिहीन दिखाई दिया। अमेरिका शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता के बजाय एक दर्शक बनकर रह गया है। सूत्र से बताते हैं कि अक्तूबर 2024 में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला को मारने के लिए किए गए हवाई हमले से पहले भी इस्राइल ने वाशिंगटन को सूचना नहीं दी थी, जो अमेरिकी इजाजत के बिना कार्रवाई करने की इस्राइल की बढ़ती इच्छाशक्ति का संकेत है। वास्तव में, गाजा में चल रहे युद्ध का लेबनान तक विस्तार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हिजबुल्ला (जो उत्तरी इस्राइल की ओर रॉकेट दाग रहा था) को रोकने के लिए इस्राइल ने दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्ला के कई उच्च पदाधिकारी मारे गए। इसके बाद अपने करिश्माई नेताओं के बिना युवाओं को भर्ती कर हिजबुल्ला खुद को फिर से उठ खड़ा करने में असमर्थ था और उसका संगठन बिखर गया। नवंबर, 2024 तक अमेरिकी मध्यस्थता में हिजबुल्ला संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया।

सैन्य और संगठनात्मक रूप से हिजबुल्ला का पतन ईरान की क्षेत्रीय शक्ति के लिए बड़ा झटका है। हिजबुल्ला एक समय दुनिया का सबसे ज्यादा हथियारों से युक्त गैर-सरकारी हिंसक संगठन था। उसके पास लगभग 50,000 लोगों की फौज और विभिन्न रेंज की दो लाख से ज्यादा रॉकेट व मिसाइलें थीं। इस्राइल के साथ छद्म युद्ध में हिजबुल्ला और हमास के कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान काफी कमजोर पड़ गया। इसके अलावा, ईरान आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। दशकों से ईरान पश्चिम एशिया में रणनीतिक वर्चस्व हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का अनुमान है कि ईरान ने 2012 से 2020 तक सीरिया में बशर अल-असद को सहारा देने के लिए 16 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए। असद के तख्तापलट के बाद सीरिया अब ईरान से हिजबुल्ला तक हथियारों की खेप या रसद पहुंचाने में सहयोग नहीं कर सकता। असद को हटाने वाले विभिन्न सशस्त्र लड़ाकों को तुर्किये के समर्थन के साथ अंकारा खुद को सीरियाई गृहयुद्ध के बाद बड़े विजेता के रूप में देखता है, न कि तेहरान।

इधर, पश्चिम एशिया में घटते अमेरिकी प्रभाव और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव की वजह से ट्रंप की खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना भी खटाई में पड़ सकती है। अमेरिका अपने राजदूत स्टीव विटकॉफ को ओमान भेजकर ईरान के साथ परमाणु समझौता करने का प्रयास कर रहा है, जिसके बदले वह ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लेगा, लेकिन वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका इस्राइल को हमले करने से नहीं रोक पाया, जिसका उसे पहले से अंदेशा था।

हालांकि, अमेरिका इस्राइल को हर साल 3.8 अरब डॉलर मूल्य के हथियारों की आपूर्ति करता है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या घरेलू राजनीतिक दबाव में अमेरिका इस्राइल को फंडिंग रोक देगा। वहीं, नेतन्याहू के लिए यह पश्चिम एशिया को नया आकार देने और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता बदलने का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अमेरिका या बाकी दुनिया उनकी इस कार्रवाई के बारे में क्या सोचती है।

(द कन्वर्सेशन से)

मौसम और हादसे

यह ऐसा समय है, जब मौसम और मौसम जनित जोखिमों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहीं भीषण गर्मी, तो कहीं मौसम जनित हादसे रुलाने लगे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर, मानसून भी बढ़ता आ रहा है। दो-तीन दिनों में ही झारखंड में प्रवेश करने वाला है। आगामी सप्ताह में मानसून उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर जाएगा। ध्यान रहे, इस साल मानसून ने सामान्य समय से आठ दिन पहले 24 मई को केरल भूमि का स्पर्श किया है और वह अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है, दस दिन के अंदर मानसून के बादल दिल्ली और हरियाणा को भी भिगोने लगेंगे। मतलब, तय समय से आठ-दस दिन पहले ही मानसून का आगमन संभव है। यह खुशखबरी की तरह है। जब सूरज की आग उगलती किरणें और गर्म हवाएं लोगों को बीमार कर डालने को तैयार दिखती हैं, तब पंखे, कूलर का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ऐसे में, जुबान पर बस यही सवाल है कि मानसून कब आएगा?

बहरहाल, सवाल यह भी है कि जहां मानसून आ गया है, वहां क्या हाल हैं या जहां बारिश हो रही है, वहां क्या स्थिति है? अगर रविवार की ही बात करें, तो मौसम की मार आपदा में बदल जा रही है। दो बहुत दुखद त्रासदियां हैं, जिन पर जरूर गौर करना चाहिए। रविवार को ही रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के वन क्षेत्र के पास हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार पायलट समेत सात लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भर रहा था और सुबह साढ़े पांच बजे दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। अब यहां अनेक सवाल खड़े होते हैं, जब मौसम ठीक नहीं था, तब हेलीकॉप्टर उड़ाने की क्या जरूरत थी? क्या निजी विमानन या यात्रा कंपनियों के लिए उनका आर्थिक लाभ मानव जीवन से भी महत्वपूर्ण हो गया है? कुछ ही दिनों के अंदर यह अपनी तरह का दूसरा हादसा है। क्या हम हवाई यात्राओं के प्रति लापरवाह होते गए हैं? क्या हम सुरक्षा या सावधानी के मानदंडों की पालना नहीं कर रहे? अब केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं अगले दो दिनों के लिए निलंबित कर दी गई हैं, मगर इस क्षेत्र में सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके अलावा, जंगलचट्टी के पास खड्ड में मलबा और पत्थर गिरने के चलते उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई है। ये दोनों हादसे इशारा हैं कि पहाड़ों पर बहुत सावधानी से यात्रा करने की जरूरत है।

देश में कहीं भीषण गर्मी सता रही है, तो कहीं मानसून का इंतजार है और कहीं मौसम जनित हादसे जानलेवा साबित हो रहे हैं। यह हर तरह से सतर्कता का समय है।

उधर, रविवार को ही पुणे में इंद्रायणी नदी पर रविवार को एक पुराना पुल ढह गया, जिसमें अनेक लोगों के मरने की आशंका है। यह एक पर्यटन स्थल है, जहां बारिश के मौसम में विशेष रूप से लोग उमड़ते हैं। रविवार होने की वजह से पुल पर हादसे के वक्त करीब सौ लोग थे। मावल तहसील के कुंदमाला इलाके के पास हुआ यह हादसा भी अनेक सवाल खड़े करता है? लोहे का पुल तीस साल पुराना था, लेकिन उस पुल पर एक साथ सौ लोगों को किसने जाने दिया? वाकई, यह मौसम ऐसा है, जब अनेक लोग अति उत्साह में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। प्रशासन तो जिम्मेदार है ही, मगर लोगों को भी अपने स्तर पर सचेत व तैयार रहना होगा, ताकि उनकी सुरक्षा से कोई समझौता न कर सके। यह समय है, जब तमाम पुराने पुलों, सड़कों, बांधों, पटरियों और वाहनों की योग्यता-क्षमता को परख लेना चाहिए।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
13 जून, 1950

खाद्य मंत्री की अपील

नई दिल्ली, 12 जून। अखिल भारतीय रेडियो के दिल्ली केन्द्र से आज एक भाषण प्रसारित करते हुए भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने लोगों से अपील की कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाये, तो वे कन्द, फल और शाक-सब्जी खाकर ही रहें। आपने कहा कि इस सप्ताह इन्हीं तीन प्रकार के खाद्यों का सेवन करके, जिनका वनों से घनिष्ठ संबंध है, हमें वनों के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करना चाहिये। श्री मुन्शी ने दोहराया कि 'देहोत्सर्ग' स्थान में, जहां भगवान कृष्ण ने देहत्याग किया था, 10,000 वृक्ष लगाये जायेंगे और दिल्ली में गांधी जी की समाधि के चारों ओर 2,000 वृक्ष लगाये जायेंगे।

श्री मुन्शी ने यह भी कहा कि वृक्षारोपण के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न के लिये तीन पारितोषिक दिये जायेंगे। पहला पारितोषिक उस जिले को दिया जायेगा, जो वृक्ष लगाने के प्रयत्न में सबसे आगे रहेगा। दूसरा पारितोषिक किसी संस्था को और तीसरा किसी व्यक्ति को दिया जायेगा। श्री मुन्शी ने अपने भाषण में कहा कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने इस वन महोत्सव को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है। मैंने बम्बई में कहा था कि आधुनिक कनाडा के 'वृक्ष पुरुषों' के समान हमें भी वृक्षों का सम्मान और उनकी पूजा करनी चाहिए। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि इस उत्सव को मनाने के संबंध में मैंने जो अपील की थी, उसका देशवासियों ने स्वागत किया है।

बम्बई में भारतीय व्यापार मंडल ने 'देहोत्सर्ग' स्थान पर 10,000 वृक्ष लगाने का वचन दिया है। दिल्ली भी राष्ट्रपिता की समाधि के चारों ओर 2,000 वृक्ष लगाने में सहायता दे रही है। पहली जुलाई को सुबह साढ़े आठ बजे हमारे प्रिय राष्ट्रपति राजघाट पर एक वृक्ष लगाकर उत्सव का श्रीगणेश करेंगे। प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री गण भी इस उत्सव में भाग लेंगे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कुछ विदेशी दूतावासों ने भी उस दिन वन महोत्सव में समाधि के समीप वृक्ष लगाने के कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। वृंदावन, कांजीवरम, पुराने कांची, तिरुपति, जगन्नाथपुरी तथा कुमारी अंतरीप में भी वृक्षारोपण के कार्य की तैयारियां हो रही हैं।

ट्रंप के अमेरिका में फैलता असंतोष

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर एवं विदेश नीति विशेषज्ञ, ओआरएफ

हमेशा की तरह बहुत से देश और लोग हैं, जो अमेरिका से शांति एवं विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर अमेरिका तो खुद अपनी समस्याओं से घिरता दिख रहा है।

ईरान-इजरायल के बीच भड़कते युद्ध के बीच बहुत से देशों को उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की पहल करेंगे। क्या यह उम्मीद पूरी होगी, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल अमेरिका खुद अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। वहां बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आज यह देखना जरूरी है कि अमेरिका कैसे हालात से गुजर रहा है।

विरोध को दबाने की कोशिश के तहत ही ट्रंप को शनिवार को राजधानी वाशिंगटन डीसी में सैन्य परेड करानी पड़ी। हजारों सैनिकों ने टैंकों, हेलीकॉप्टरों व विमानों के साथ अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस के जश्न में नेशनल मॉल से मार्च किया, जबकि पूरे देश में लाखों लोगों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। गौर करने की बात है, साल 1991 के बाद से अमेरिका की राजधानी में यह पहली सैन्य परेड थी और यह उस दिन हुई, जब ट्रंप 79 वर्ष के हुए।

प्रदर्शनकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच लगातार झड़पें; शहर-दर-शहर कर्फ्यू; एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालय को दी जा रही चुनौती; कैद किए जा रहे छात्र और सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा एक-दूसरे से असहमतियों का खुला इजहार, राजनीतिक हत्याएं, यह तस्वीर तीसरी दुनिया के किसी तानाशाही वाले देश की नहीं, आज के अमेरिका की है। लॉस एंजिल्स की सड़कों ने पिछले कुछ दिनों में जो भयंकर आग देखी, इसकी लपटें अमेरिका के कई प्रमुख शहरों तक फैल गई हैं, मगर व्हाइट हाउस की नीतिगत पहल पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका के सामाजिक-राजनीतिक विकास के लिहाज से एक निर्णायक क्षण के रूप में उभर रहा है। दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक नजीर रहा अमेरिका आज सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है, जो हमें विकासशील दुनिया के अनेक देशों की याद दिलाता है। वाशिंगटन के राजनीतिक पंडित इन देशों को शासन करने के तरीके की नसीहतें देते रहते हैं। लॉस एंजिल्स में पिछले हफ्ते से ही विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। मुख्यतः आप्रवासन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग द्वारा अप्रवासियों को निशाना बनाकर छापे मारे जा रहे हैं, जिसके जवाब में पूरे शहर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। बढ़ती अशांति को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजिल्स में 2,000 नेशनल गार्ड और 700 मैरीन सैनिकों की तैनाती कर दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास सहित अनेक स्थानीय अधिकारियों ने इस कदम की आलोचना की है, हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है।

अमेरिका की घरेलू राजनीति में आप्रवासन एक बड़ा विभाजनकारी मुद्दा बन गया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे लेकर कई आक्रामक नीतियां लागू की हैं, जिनसे इस मसले पर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है और बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। अनुमान है, ट्रंप के कार्यकाल में लाखों अवैध आप्रवासियों को अमेरिका से निकाला जाएगा। इन कदमों के समर्थन के लिए उन्होंने 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' भी पेश किया है। यह एक व्यापक विधायी प्रस्ताव है, जो इन कदमों के लिए अरबों डॉलर आवंटित करता है। इनमें सालाना दस लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने और सीमाओं पर दीवार खड़ी करने के लिए धन मुहैया कराना शामिल है।

जाहिर है, राजनीतिक विभाजन साफ-साफ दिखाई पड़ रहा। रिपब्लिकन जहां बड़े पैमाने पर ट्रंप प्रशासन के नजरिये का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेट नागरिक आजादी, मानवाधिकारों और इतने बड़े पैमाने पर निष्कासन के आर्थिक प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। गवर्नर गैविन न्यूसम ने, जो डेमोक्रेट नेता और राष्ट्रपति के प्रमुख आलोचक हैं, लॉस एंजिल्स में सैन्य तैनाती को एक 'तानाशाह राष्ट्रपति की विक्षिप्त कल्पना' बताया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर लगातार दोहरा रहे हैं कि व्हाइट हाउस को आशा है कि आव्रजन व सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग एक दिन में 3,000 तक गिरफ्तारियां कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की गिरफ्तारियों के मुकाबले यह कई गुणा अधिक है। ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिकी सड़कों पर वामपंथी अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे मुक्ति पाने के लिए बतौर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करेंगे।

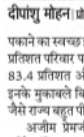

मगर इस सबसे अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण गहराता जा रहा है। देश की दो प्रमुख सियासी पार्टियों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच की वैचारिक खाई और चौड़ी हो गई है। दोनों ही पार्टियां बीच की स्थिति से दूर होती जा रही हैं। यह बदलाव कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिखता है, जहां पिछले पांच दशकों में सदस्यों की विचारधाराएं अधिक चरम पर पहुंच गई हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें आपसी सहयोग कम हो गया है।

ध्रुवीकरण शैक्षिक तौर भी साफ-साफ दिख रहा है। डेमोक्रेट्स उच्च शिक्षित व्यक्तियों के साथ अधिक जुड़े हुए हैं, जबकि रिपब्लिकन उन मतदाताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। इस विभाजन ने बिल्कुल विपरीत विचारों को जन्म दिया है। डेमोक्रेट जहां प्रामाणिक विशेषज्ञों का पक्ष लेते हैं, तो वहीं रिपब्लिकन विश्वविद्यालयों और मीडिया संस्थाओं के प्रति संदेह जताते हैं। बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण विधायी गतिरोध पैदा हो रहा है। कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल को कांग्रेस से पारित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा, आप्रवासन और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस गतिरोध के शिकार बन गए हैं। जाहिर है, ऐसे गतिरोध लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करते हैं और दबाव वाले मुद्दों से निपटने में सरकार की क्षमता को प्रभावित करते हैं।

अमेरिका एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कई लोगों का तर्क है कि एक राष्ट्र के तौर पर इसे ऐसे नुकसान होने जा रहे हैं, जिनकी भरपायी न हो सकेगी। हालांकि, अमेरिका में अपनी मूल शक्तियों को बार-बार हासिल करने की महान प्रवृत्ति है। फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी एलेक्सिस डी टोकेविले ने कहा था, 'अमेरिका की महानता किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक प्रबुद्ध होने में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने की उसकी क्षमता में है।' यह देखना अभी बाकी है कि क्या ट्रंप का अमेरिका ऐसे क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप में घरेलू असंतोष के न्यायपूर्ण समाधान और दुनिया में अमन-चैन लाने की क्षमता या इच्छा है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

गरीबी तो घटी, पर गरीबों का जीवन ज्यादा नहीं बदला

दीपांशु मोहन | प्रोफेसर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी

हाल ही में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2011-12 में भारत में चरम गरीबी 27.1 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3 प्रतिशत रह गई। इस दौरान लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी-रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह निष्कर्ष गरीबी आंकने के तरीके पर सवाल खड़े करता है। क्या हम भारत में कुछ ही लोगों को गरीब मान रहे हैं या गरीबी के पूरे दायरे को समझने में विफल हो रहे हैं?

भारत में गरीबी मापने का पैमाना मुख्य रूप से आय या उपभोग है। यह अभाव के बारे में बहुत कुछ नहीं कहता। तेंदुलकर समिति और बाद में रंगराजन समिति ने उपभोग के तरीके में आ रहे बदलाव को दर्शाने के लिए गरीबी रेखा में सुधार तो किया, पर मानदंड आय को ही बनाए रखा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) सहित सभी मानक इस बात पर जोर देते हैं कि गरीबी के आकलन में शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन स्तर के अभावों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आलोचकों का कहना है, महामारी के बाद बिना किसी जमीनी सर्वेक्षण के केवल अनुमानित आंकड़ों पर आधारित ये निष्कर्ष प्रगति की टेढ़ी-मेढ़ी तस्वीर पेश करते हैं। ये लोगों को मिली सुविधाओं या व्यवस्था की कमियों को ठीक से सामने नहीं लाते।

जब तक आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय असमानताएं बनी रहेंगी, तब तक गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई खत्म नहीं हो सकती।

गरीबी घटने के इस अनुमान को मान भी लें, तो यह किसके फायदे में है? आय में वृद्धि तो हुई है, पर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं तक लोगों की पहुंच में कमी बनी हुई है। बहुसंख्यक आबादी के लिए इन सुविधाओं को प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 2011-12 में 65 प्रतिशत तक अति-गरीबी थी। अब देश में जो गरीबी में कमी दर्ज की गई है, उनमें इन राज्यों में ही दो-तिहाई तक कमी बताई गई है। मगर 'असमानता सूचकांक रिपोर्ट 2025' में इन राज्यों में विषमता की तस्वीर अधिक गहरी है। असमानता सूचकांक पांच कसौटियों- बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सेवा और कानूनी मदद की उपलब्धता पर राज्यों का आकलन करता है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार 'आकांक्षी' श्रेणी में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 19 प्रतिशत और बिहार में 21.5 फीसदी परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन मिल पाता है। उधर, गोवा में 90 प्रतिशत परिवार पक्के घरों में रहते हैं, जबकि केरल में 83.4 प्रतिशत और तमिलनाडु में 87.9 प्रतिशत हैं। इनके मुकाबले बिहार, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बहुत पीछे हैं।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021' रिपोर्ट द्वारा घरेलू आय के आंकड़ों का विश्लेषण कोविड के आर्थिक प्रभाव को उजागर करता है। इस विश्लेषण के अनुसार, सबसे निचली 10 प्रतिशत आबादी की आय में 27 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई, जबकि 40 से 50 फीसदी आबादी की आय में 23 प्रतिशत व शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों की कमाई में 22 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसी तरह 'हंगर वॉच सर्वेक्षण' ने 2022 में बताया कि 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने किसी न किसी रूप में खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया, जिसमें 25 प्रतिशत गंभीर संकट (जैसे भूखे रहने) में थे। सर्वेक्षण के शुरुआती महीने में 41 प्रतिशत लोगों ने अपने आहार की पोषण गुणवत्ता में गिरावट की शिकायत की, जबकि 67 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे रसोई गैस खरीदने में असमर्थ हैं। 2022 में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि महामारी के कारण भारत में लगभग साढ़े सात करोड़ नए लोग गरीबी की खाई में चले गए। बाद में 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023' के अध्ययन में भी इसकी पुष्टि की गई।

पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना व आयुष्मान भारत जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों ने लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने और नगदी हस्तांतरण में सुधार किया है, पर चुनौतियां कायम हैं। इनकी बारीकी से जांच करने पर हकीकत पता चलेगी। हमें संस्थागत क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति व सार्वजनिक वस्तुओं के समान वितरण पर ध्यान देना चाहिए।

(साथ में अदिति देसाई)

मनसा वाचा कर्मणा

छाया पकड़ने की कोशिश

दुनिया में इतने ज्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और तरह-तरह के प्रार्थनाघर हैं, लोगों की लंबी-लंबी कतारें उनमें लगी हुई हैं, करोड़ों का कारोबार चलता है, फिर भी दुनिया परमात्मा की उपस्थिति से रिक्त मालूम होती है। एक आध्यात्मिक सूनापन लगता है, कोई सुकून नहीं दिखाई देता। इतनी हिंसा, इतने उपद्रव क्या भगवत्ता का प्रमाण देते हैं?

ओशो का निदान है कि असली परमात्मा से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमने उसकी अनगिनत छाया बना ली हैं। तरह-तरह की मूर्तियां बनाकर हम अपनी सांत्वना कर लेते हैं कि यही परमात्मा है। लेकिन ये छाया हैं, इनका मूल जो है, वह तो चेतना है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। हमने प्रार्थना को पहले रख लिया है और परमात्मा को पीछे। प्रार्थना यानी मांग। हमने छाया को पहले रख लिया है और मूल को पीछे। छाया को पकड़ने चले हैं और मूल पकड़ में आता नहीं।

एक कहानी है। सुबह की धूप में घर के आंगन में एक बच्चा खेल रहा था और अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश में जुटा था। वह अपनी छाया पर झपट्टा मारता, मगर छाया पकड़ में नहीं आती, तो रोता-चिल्लाता और फिर से झपट्टा मारता। उसकी मां उसे समझाए जा रही थी कि बेटा, छाया पकड़ में नहीं आती! मगर वह मानता ही नहीं था। छाया सामने दिखाई पड़ रही, तो पकड़ में क्यों नहीं आएगी? यह तो रही हाथ भर की दूरी पर। तो वह फिर उसकी ओर सरकता, फिर पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह जैसे ही साया की ओर सरकता, छाया भी आगे सरक जाती।

द्वार पर एक फकीर आया। वह बच्चे की चेष्टा देखकर हंसने लगा। उसने उसकी मां से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं समझा सकता हूं इस बच्चे को। मां थक गई थी। उसने कहा, जरूर आइए, सुबह से मुझे परेशान किए हुए है, काम भी नहीं करने देता। छाया पकड़ना चाहता है! छाया भी कहीं पकड़ी जाती है? फकीर ने कहा, पकड़ने का ढंग होता है। उसने बच्चे का हाथ लिया और उसके ही सिर पर रख दिया। तुरंत उसकी छाया बदल गई। इधर बच्चे का हाथ सिर पर गया, उधर छाया भी पकड़ में आ गई। बच्चा खिलखिलाने लगा।

हमने प्रार्थना को पहले रख लिया है और परमात्मा को पीछे। प्रार्थना यानी मांग। हमने छाया को पहले रख लिया है और मूल को पीछे। छाया को पकड़ने चले हैं और मूल पकड़ में आता नहीं।

अपने को पकड़ने से छाया पकड़ में आ गई। मूल को पकड़ा, तो छाया पकड़ में आ गई। यह गहरा सूत्र है उन सबके लिए, जो बाहर खोज रहे हैं। बाहर लोग जो खोज रहे हैं, वे सब छाया हैं। ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके ही निर-अहंकार भाव-दशा का नाम है! वह कोई व्यक्ति नहीं, वह कोई आकाश में स्वर्ण-सिंहासन पर विराजमान जगत का शासक नहीं। परमात्मा है आपकी ही वह विशुद्ध स्थिति, जब अहंकार की जरा सी भी मात्रा शेष नहीं रह जाती।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

पिछले एक दशक में जबरन विस्थापित किए गए लोगों की तादाद लगभग दोगुनी हो गई है। धरती के प्रत्येक 67 में से एक व्यक्ति को अपना घर-बार छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा है।

अब निजी ब्रांड गढ़ रहा सोशल मीडिया

सोशल मीडिया के अब कई सकारात्मक रूप सामने आ रहे हैं। मगर इसमें किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या पर्सनल ब्रांड को बनाना पेड़ लगाने या बच्चे को पालने जैसा काम है। यह एक दिन में नहीं बनता। इसको बनाने के लिए लगातार प्रयास चाहिए। प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांड के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन यह पर्सनल ब्रांड क्या है? तो इसे यूं समझिए कि टाटा नमक एक प्रोडक्ट ब्रांड है, टाटा स्काई सर्विस ब्रांड और स्वयं रतन टाटा एक पर्सनल ब्रांड हैं। जैसे बहुत लोग मुझे इन्सेन्स मीडिया के नाम से जानते हैं और इन्सेन्स को मुझसे। ज्यादातर लोग पर्सनल ब्रांड को बिल्कुल आगे नहीं रखते और सिर्फ बिजनेस ब्रांड पर फोकस करते हैं। मगर आपका पर्सनल ब्रांड आपके बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। गौर कीजिए, आज ब्रांड नरेंद्र मोदी से पूरी भाजपा की नैया पार लग रही है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलग पर्सनल ब्रांड बनाया है।

कल मैं अहमदाबाद में था, एक मित्र ने कहा कि मैं एक सोशल मीडिया एजेंसी हायर कर रहा हूं अपने अगरबत्ती ब्रांड के प्रमोशन के लिए। मैंने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन आपके ब्रांड को प्रमोट कैसे करना है, एजेंसी को आप कैसे समझाओगे? उन्होंने कहा, यह तो उसका (एजेंसी का) काम है, अपने आप करेगी। मैंने कहा, अपने बच्चे की परवरिश आया के हाथों करानी है या उसे खुद संभालना है, यह पूरी तरह से निजी और परिस्थितिजन्य मामला है। संभव है, आपके पास बिल्कुल समय न हो और आया ही आपके बच्चे को संभाले, लेकिन आया की परवरिश और आपकी परवरिश के आउटपुट में अंतर होगा।

लोग आपकी छोटी-छोटी गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं। आपको महीनों-सालों तक ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपके बारे में एक धारणा बनाते हैं, यह धारणा ही आपका पर्सनल ब्रांड है। आपको लगेगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्क्रॉल करते हैं, बगैर कोई प्रतिक्रिया दिए। फिर एक दिन वे आपसे कहेंगे, आपकी दो साल पहले की गई वह पोस्ट पढ़ी थी, तभी से आपके साथ जुड़ना चाहता था।

भारत में 140 करोड़ पर्सनल ब्रांड हैं। सवाल है, कौन इसे कैसे 'कैरी' करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योगपति, खिलाड़ी या अभिनेता-नेता ही पर्सनल ब्रांड हैं, आप अगर नौकरी भी करते हैं, तब भी आप एक पर्सनल ब्रांड हैं। एक से दूसरी संस्था में जाने पर वह संस्था आपके साथ नहीं जाती, आपका पर्सनल ब्रांड साथ जाता है। इसलिए अपने पर्सनल ब्रांड में निवेश कीजिए, यह अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सोशल मीडिया तेजी से ऐसे ब्रांड गढ़ रहा है।

दीपक गोयल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
सोशल मीडिया

सिर्फ छवि ध्वस्त करने का यह माध्यम

सोशल मीडिया आज के युग की एक बड़ी सच्चाई है। मगर कई मामलों में यह खतरनाक दानव साबित हो रहा है। अभी तक यह किसी जिम्मेदार तंत्र के नियंत्रण में नहीं है, ताकि इस पर पोस्ट की जाने वाली सामग्रियों की प्रामाणिकता की जवाबदेही तय की जा सके। किसी पोस्ट के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मामला बनने पर ही सरकारी या गैर-सरकारी हस्तक्षेप से संबंधित सामग्री का नियमन होता है, वह भी नाममात्र का। और जब तक नियमन की प्रक्रिया पूरी हो पाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पोस्ट करने वाला अपने मूल उद्देश्य में, यानी आपकी छवि ध्वस्त करने के इरादे में सफल हो चुका होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रामक जानकारियां पोस्ट की जाती हैं। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं या उनको साझा करते हैं, तो आपकी छवि को गहरा धक्का लग सकता है। इस माध्यम के सबसे बड़े खलनायक हैकर्स हैं, जो आपकी निजी जानकारियों या संदेशों तक पहुंच जाते हैं।

सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग अवसाद, तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके विभिन्न मंचों पर अक्सर ऐसी तस्वीरें चर्चा बटोरती हैं, जो वास्तविक नहीं होतीं। इन तस्वीरों के देखकर आप संबंधित व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। इस पर लोग अक्सर दूसरों की तुलना में अपने जीवन को खुशहाल दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे आप कुंठा के शिकार हो सकते हैं। आजकल मेट्रो में आप देखें, हर यात्री अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम या वाट्सएप ग्रुप में डूबा मिलेगा। कोई किसी से संवाद करता हुआ कम दिखता है। इस तरह ये मंच दिन-ब-दिन आपको दूसरों से काट रहे हैं। ऐसे में, आपमें अकेलापन और अलगाव की भावनाएं मजबूत हो सकती हैं, जिनसे आपको नुकसान ही होगा। सोशल मीडिया पर यदि आपने गलत जानकारी साझा की या कोई फर्जी वीडियो या फोटो पोस्ट की, तो बेमतलब कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।

सोशल मीडिया युवाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक साबित हो रहा है। पश्चिम में कई शोध इसका खुलासा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश इसके नियमन के ठोस कानून बना रहे हैं। बच्चों का स्क्रीन पर ज्यादा समय न सिर्फ उनकी आंखों को प्रभावित कर रहा, बल्कि उन्हें उन व्यावहारिक ज्ञान से दूर कर रहा, जो जिंदगी भर काम आते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि सोशल मीडिया से पर्याप्त दूरी बरती जाए। हमें लोगों को सोशल मीडिया की सीमाएं बताने, इसके उपयोग का मॉडल बनाने और बच्चों को इसका सुरक्षित उपयोग सिखाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

निरंजन दास, टिप्पणीकार

चिंतन

स्कूल से महरूम बच्चों की संख्या में वृद्धि चिंतनीय

विश्व की सरकारें प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक लक्ष्य का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। दुनिया भर में 27.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। साफ है कि ये बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। भारत में करीब 14 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जबकि देश में सरकारें बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए मिड डे मिल से लेकर मुफ्त शिक्षा तक के अनेक कार्यक्रम चला रही हैं। भारत में पिछले 12 से 13 वर्ष में गरीबी दर में काफी गिरावट आई है, इससे आर्थिक प्रगति का पता चलता है, लेकिन स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों, स्कूल से ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों, माध्यमिक शिक्षा तक का सफर तय नहीं कर पाने वाले बच्चों और उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाने वाले बच्चों की संख्या में अपेक्षित गिरावट नहीं आई है। भारत में अत्यधिक गरीबी से सामान्य गरीबी में जीने वाले परिवारों की बड़ी संख्या की वजह से शिक्षा इनकी प्राथमिकता नहीं रह पाती है। भारतीय स्कूलों में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन बच्चों के लिए किताब, कलम कॉपी से लेकर भोजन और वस्त्र के इंतजाम गरीब परिवारों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। गरीब परिवार अपने गुजर-बसर में अपने बच्चों को शामिल कर लेते हैं। यह स्थिति दुनिया भर में देखी जाती है। गरीबी और शिक्षा का सीधा संबंध है। विश्व की कई सरकारें अपनी शिक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हवाले छोड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम (जीईएम) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में आशंका जताई है कि 2025 के अंत तक देश शिक्षा के अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों से पिछड़ सकते हैं। अभी 27 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यह संख्या पिछले वर्ष से 2.1 करोड़ अधिक है। मतलब साफ है कि स्कूल न जाने वालों की संख्या में कमी आनी चाहिए, उल्टे यह बढ़ रही है। विश्व की सरकारों का प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर फोकस नहीं है। धार्मिक रूढ़िवाद भी शिक्षा के लक्ष्य हासिल करने में बाधा बन रहे हैं। अफगानिस्तान समेत कुछेक कट्टर इस्लामिक सोच वाली सरकारें हैं, जो लड़कियों की शिक्षा को रोक रही हैं। स्कूलों में नए नामांकन में वैश्विक स्तर पर कमी आई है। शिक्षा मूलभूत अधिकार है, सबके लिए, इसके बावजूद कई कट्टर इस्लामिक सरकारें हैं, तो बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग को अवरूद्ध कर रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान में माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्व भर में सैन्य संघर्ष बढ़ने व हमले होने के चलते भी स्कूल शिक्षा को धक्का लगा है, प्रभावित क्षेत्र में बच्चों का सुरक्षित स्कूल पहुंचना मुश्किल हुआ है। जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते यूनेस्को के अनुमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर सरकारों को अपने-अपने मुल्क में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में उत्तर प्रदेश, असम व झारखंड ऐसे राज्य हैं, जहां स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है। एक सर्वे के मुताबिक, भारत में तकरीबन 2 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए। भारत में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के बावजूद अगर शत प्रतिशत बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो यह सरकारों की बड़ी विफलता है। बेहतर नागरिक का निर्माण राज्य का संवैधानिक दायित्व है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चे स्कूल में हों।

विश्लेषण
शिवप्रकाश

रक्षा क्षेत्र में मजबूत बन रहा भारत

गरीब कल्याण, ढांचागत विकास, अंतर बाह्य सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक उत्थान एवं विदेशों में बढ़ता भारतीय सम्मान सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां 11 वर्ष में प्रगति की गवाह हैं। भारत सहित विश्व की अनेक संस्थाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने इस ऐतिहासिक सफलता की प्रशंसा की है। रक्षा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं। आयात में 21% की कमी करके 11 वर्षों में निर्यात में 34% की वृद्धि करने में देश सक्षम हुआ है। आज हम लगभग 80 से अधिक देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' में हमारे स्वदेशी शस्त्रों की सफलता को देखकर विश्व में हमारे शस्त्रों की मांग भी बढ़ गयी है।

हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है। संपूर्ण देश में मोदी सरकार की सफलता पर प्रेस वार्ताएं, प्रदर्शनी, विचार संगोष्ठी, जनसभाएं एवं ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सोशल मीडिया द्वारा योजनाओं की जानकारी एवं अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो रहा है। गरीब कल्याण, ढांचागत विकास, अंतर बाह्य सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक उत्थान एवं विदेशों में बढ़ता भारतीय सम्मान सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां 11 वर्ष में प्रगति की गवाह हैं। भारत सहित विश्व की अनेक संस्थाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने इस ऐतिहासिक सफलता की प्रशंसा की है। रक्षा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं।

चाणक्य नीति में कहा कि "शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते" अर्थात शास्त्रों की चर्चा भी तभी संभव है जब राष्ट्र सभी प्रकार से सुरक्षित हो। सिद्धांत कितना भी श्रेष्ठ हो, उसकी सफलता उस सिद्धांत का अनुसरण करने वालों की शक्ति पर ही निर्भर करती है। इसी कारण विद्वानों ने शक्ति को ही शांति का आधार बताया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता 'क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो' इस सिद्धांत को ही प्रतिपादित करते हैं। भारतीय जनसंघ ने अपने 1964 के पटना अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की थी कि भारत को परमाणु बम बनाने के सभी प्रयत्न करने चाहिए। "सिद्धांत एवं नीतियां" नामक दस्तावेज में भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने की बात की थी। प्रस्ताव प्रतिपादन करते समय कहा गया था कि हमारे आराध्य सभी देवी-देवता धर्म संस्थापना के लिए शस्त्रधारी हैं। इसलिए भारत माता भी परमाणु बम धारी होनी चाहिए। इसी नीति का अनुसरण करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1999 में पोखरण परमाणु विस्फोट कर विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश अपने हितों की सुरक्षा करने में समर्थ बने, इस प्रकार की नीति पर चला। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी का उदाहरण है। जहां कांग्रेस सरकार में आतंकियों के लिए 'जी' जैसे सम्मानपूर्वक शब्दों का उपयोग एवं 'बिरयानी खिलाना' जैसे उपक्रम चल रहे थे वहीं मोदी सरकार में सेना और सुरक्षा बलों को आतंक से लड़ने के लिए छूट एवं सुरक्षा बलों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये गए। रक्षा क्षेत्र का बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था, अब 2025-26 के लिए वह बढ़कर 6.81 लाख करोड़ अर्थात तीन गुना से अधिक हो गया है। 2015 कैग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के पास केवल 20 दिन का गोला बारूद उपलब्ध था। व्यक्तिगत सैनिक स्तर पर, सैनिकों को अब स्वदेशी रूप से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली बुलेटप्रूफ जैकेट, उन्नत हेलमेट, नई बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म, नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेजर उपलब्ध करायी गई हैं। मोदी सरकार के आने के बाद सेना के समन्वय के लिए लंबित मांग सीडीएस की नियुक्ति का निर्णय हुआ। ऑपरेशन सिन्दूर में तीनों सेनाओं के समन्वय में हमने इस निर्णय की भूमिका को अनुभव किया है। शस्त्रों की खरीद के लंबे

समय से लंबित निर्णयों का भी शीघ्र निस्तारण होते हुए हम देख चुके हैं। फ्रांस से आने वाले राफेल की खरीद इसी प्रक्रिया का परिणाम है। एस-400, सुखोई -30, इजरायल से ड्रोन, हैमर मिसाइल, चिनूक हेलिकॉप्टर, एलसीएच प्रचंड (लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर), तेजस फाइटर जेट (पूर्ण स्वदेशी विमान), पिनाका रॉकेट सिस्टम (मल्टी बैरल राकेट लांचर) , वरुणास्त्र आदि की उपलब्धता के कारण भारतीय सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में गिनी जाती है। ऑपरेशन सिन्दूर में निर्धारित लक्ष्य पर मार एवं शत्रु के ड्रोन एवं मिसाइल को मार गिराने में हम सक्षम हुए हैं। 11 वर्ष के सफलतम कालखंड में केवल विदेशों से शस्त्र खरीद ही नहीं, हमने स्वयं के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को भी पहचाना है। अब हम भारत में उन्नत एवं आधुनिक स्वदेशी शस्त्रों का निर्माण भी कर रहे हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रुस्तम यूएवी ड्रोनसका डीआरडीओ द्वारा लखनऊ में निर्माण, रूस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,टाटा -डसाल्ट के साथ राफेल के मुख्य भाग का हैदराबाद में हम निर्माण करने वाले हैं। रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 174% की वृद्धि हुई है। रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46529 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 127265 करोड़ हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 नवंबर 2021 (राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, झांसी) के अपने संबोधन में कहा कि "भारत अपनी रणनीतिक व सुरक्षा आवश्यकताएं अन्य देशों पर निर्भर होकर पूरा नहीं कर सकता ... सरकार निरंतर 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में प्रयासरत है।" रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति के कारण अब हम खरीदने अर्थात आयात करने वाले देश नहीं, हम बेचने वाले अर्थात निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। 2004 से 2014 अर्थात 10 वर्षों में हमने 4312 करोड़ का निर्यात किया था। 2014 से 2024 में 88,319 करोड़ का हुआ है। 2024 - 25 में केवल एक वर्ष में ही हमने 23622 करोड़ का निर्यात किया है। आयात में 21% की कमी करके 11 वर्षों में निर्यात में 34% की वृद्धि करने में देश सक्षम हुआ है।

आज हम लगभग 80 से अधिक देशों में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे स्वदेशी शस्त्रों की सफलता को देखकर विश्व में हमारे शस्त्रों की मांग भी बढ़ गयी है। देश को नक्सल मुक्त करने के मोदी सरकार के संकल्प ने देश के सामान्य नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास जगाया है। नक्सली हिंसा में लिप्त आतंकी अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। 2014 में नक्सल आतंकवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। 11 वर्षों बाद 2025 में वह संख्या मात्र 6 रह गई है। बड़े-बड़े इनामी नक्सली आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। सरकार के नक्सलमुक्त देश के संकल्प से लगता है कि भावी पीढ़ी नक्सलवाद नाम ही भूल जाएगी। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, जिसमें औपनिवेशिक 'सेंट जॉर्ज क्रॉस' को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित अष्टकोणीय प्रतीक को स्थान दिया गया। खून एवं पानी एक साथ नहीं बहेगा सिंधु नदी समझौता रद्द कर हमने आतंक के प्रति अपने दृष्टिकोण को विश्व के सामने स्पष्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने, आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सम्मुख रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल देश की एकजुटता को प्रकट करने का कूटनीतिक सराहनीय प्रयास है। भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह प्रयास देश की जनता में यह विश्वास जगाने में सफल हुए हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

पर्यावरण
ज्ञानेन्द्र रावत

थम नहीं रहा देश में बढ़ती गर्मी का कहर

आजकल भीषण गर्मी के कहर और लू की भयावहता से सर्वत्र त्राहि-त्राहि मची है। गर्मी ने सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस भीषण गर्मी के चलते जहां लोग हाय-हाय कर रहे हैं, वहीं हजारों-लाखों लोग गर्मी जनित बीमारियों की चपेट में आकर मौत के मुंह में जाने को मजबूर हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सब तेज गर्मी से झुलस रहे हैं। हालत यह है कि दिन के साथ रातें भी गर्म हैं। लू अर्थात हीटवेव की तीव्रता और घातकता में दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आईपीई ग्लोबल और इसरो इंडिया के अध्ययन की मानें तो अगले पांच सालों में यानी 2030 तक देश के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, ठाणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद और पटना जैसे शहरों में लू के दिन दोगुने हो जायेंगे। यही नहीं, देश के 69 फीसदी तटीय जिले 2030 तक जून से लेकर सितम्बर के लम्बे समय तक भीषण गर्मी की मार झेलेंगे। मौजूदा समय में देश के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय और मणिपुर आदि राज्यों के 84 फीसदी जिले चरम लू जैसी स्थिति की चपेट में हैं। देश की राजधानी दिल्ली बीते पांच दिनों से भट्ठी की तरह तप रही है। राजस्थान का गंगानगर जिला और पंजाब का बठिंडा जिला 48 डिग्री को पार कर गया है। देश के उत्तर, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू से होने वाली मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों की मौतों को लेकर जारी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, दिल्ली समेत 11 राज्यों को कमजोर वर्गों खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल समुचित एवं एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार बीते 22 महीनों में से 21 महीने धरती का तापमान पूर्व औद्योगिक काल वर्ष 1850 से 1900 तक के औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। जबकि 2024 से मई 2025 की अवधि में वर्ष 1850- 1900 बेंचमार्क की तुलना में धरती 1.57 डिग्री सेल्सियस गर्म रही। असल में धरती का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह समूची दुनिया के लिए ख़तरनाक संकेत है। यह भी कि तापमान में बढ़ोतरी नित नए-नये कीर्तिमान बना रही है। बीते दस सालों ने तो धरती के सर्वाधिक गर्म होने का रिकार्ड कायम किया है। फिर यह कि साल दर साल तापमान में बढ़ोतरी के रिकार्ड ध्वस्त हो रहे हैं। चिंता इस बात की है कि भविष्य में इस पर अंकुश की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। इसका कारण तापमान को नियंत्रित करने के सारे प्रयासों का अभी तक नाकाम साबित होना है। दुनिया के शोध और अध्ययन भी इसका खुलासा करते हैं कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के बिना बेतहाशा बढ़ती गर्मी पर अंकुश की फिलहाल उम्मीद ही बेमानी है। मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, गर्मी से बचने और शरीर में पानी की कमी होने से बचने की सलाह दी है। जरूरी हो तभी बाहर निकलें और मुंह पर कपड़ा बांधें ताकि लू ना लगे। डॉक्टर दिन में कम से कम आठ से दस गिलास पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। वैस्टर्न आस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक धरती 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है। यदि तापमान में गिरावट नहीं हुई तो यह ग्रह किस दिशा में जाएगा,यह कहना बहुत मुश्किल है। धरती के तापमान में बढ़ोतरी के कारणों में ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है ही, अल नीनो भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड का सतत उत्सर्जन, सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, वनों के तेजी से होते विनाश, कार्बन फ्लोरो कार्बन गैसों का सतत उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का दहन आदि की भी अहम भूमिका है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव ने दुनिया के हर महाद्वीप को प्रभावित किया है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने और इससे मिट्टी की नमी कम होने से कई क्षेत्र सूखे का सामना करेंगे। नतीजतन फसलों की पैदावार में कमी आने से खाद्य असुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। जलाशयों में पानी का भंडारण कम होने और भूजल का स्तर गिरते जाने से जल संकट गहरायेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सादा जीवन जियें। अधिकाधिक पौधारोपण करें, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। हमें प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना होगा। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना होगा, तभी धरती बची रह पाएगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं?

संकलित
दर्शन

जब ईश्वर का वास हृदय में माना गया है, तो मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं? मंदिरों की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि पूजा, अर्चना और यज्ञ आदि द्वारा पवित्र तन्मात्रओं यानी पंचभूतों के सूक्ष्म रूप की सृष्टि की जाए। किसी साधु हृदय व्यक्ति को पूजा का कार्यभार सौंपा जाए। स्थान का मन पर अदृश्य प्रभाव पड़ता है। चिकित्सालय में व्यक्ति को हर तरफ रोग और रोगी ही दिखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी वहां अशक्त महसूस करने लगता है। हमारे शरीर से प्रतिदिन शुभ या अशुभ अदृश्य सूक्ष्म शक्ति-राशि का उत्सर्जन होता रहता है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध और आलस्य बाहर छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से जाता है। यह सामूहिक भक्ति या उपासना शुभ तन्मात्रओं व तरंगों का सृजन करती है। अतः यहां आगमन दुर्बल मन वाले मनुष्यों में ऊर्जा का संचार करता है। सज्जनों से ही प्रार्थना स्थलों की पवित्रता बनी रहती है। यदि मंदिर में असाधु व्यक्तियों का आवागमन बढ़ जाए तो स्थान अपनी पवित्रता खोने लगता है। पवित्र श्रवण मास में शिवलिंग पर दुग्ध, बेलपत्र, फल-फूल आदि चढ़ाकर पुण्य अर्जित करने की होड़ लगी रहती है। यदि ईश्वर है और वह हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होता है तो वह एक बेलपत्र, अंजुली भर दूध या एक पुष्प से भी प्रसन्न हो जाएगा। सावन के महीने से इतर भी ये दृश्य आमतौर पर मंदिरों में आम होते हैं। यदि यह व्यवस्था सुचारु न हो तो अव्यवस्था स्वाभाविक है। इसी कारण कई मंदिरों में व्यक्तिगत रूप से भोग-अर्पण की मनाही है।

महिमा राम नाम की

संकलित
प्रेरणा

एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बन्द होने से पहले अकेला फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया। और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया छुट्टी का वक्तत था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया की कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया की दो-तीन घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो, भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। एक घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रिज रूम में खट-खट की आवाज हुई। दरवाजा खुला चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब मैं 20 साल से यहां काम कर रहा हूं। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूं लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो, जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंस कर राम-राम करते हो और हालचाल पूछते हो और निकलते हुए आपका राम-राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा।

अंतर्मन

आज की पाती

और अलर्ट हों विमान कंपनियां

बीता गुरुवार हमारे देश के लिए बहुत ही अभागा दिन रहा। अहमदाबाद में उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में एक यात्री विमान आग का गोला बन गया और इस अभागे विमान में बैठे यात्रियों के साथ-साथ वहां जहां यह विमान टकराया और जहां इस जलते विमान के हिस्से गिरे, वहां के लोगों की मौत का कारण भी बन गया। जिस किसी ने भी इस दर्दनाक हादसे की खबर सुनी, वो स्तब्ध है। इस अभागे विमान के हादसे के क्या कारण रहे, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस दुखद हादसे से यह तो साफ जाहिर है कि इनसान विज्ञान के क्षेत्र में अपने आपको बेशक तीसमार खां समझता हो, लेकिन वह इस क्षेत्र में अभी भी अधूरा नजर आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विमान की तकनीकी खराबी का पहले पता चल गया होता। विमान कंपनियों को और अलर्ट रहने की जरूरत है।

- रविंद्र चौहान, राजनांदगांव

करंट अफेयर

कश्मीरी हिंदुओं ने ह्यूस्टन में मनाई ज्येष्ठ अष्टमी

टेक्सास भर से 150 से अधिक कश्मीरी हिंदू परिवार ज्येष्ठ अष्टमी और खीर भवानी पर्व मनाने के लिए ह्यूस्टन के 'हिंदू वर्शिप सोसाइटी' मंदिर में इकट्ठा हुए और उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां रागन्या देवी की पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान में हिस्सा लिया और पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार मंदिर में खीर, दूध, फूल चढ़ाए तथा दीपक जलाए। देवी खीर भवानी माता दुर्गा का एक ही एक रूप हैं जिन्हें कश्मीरी पंडित कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। ह्यूस्टन में 35 वर्ष से अधिक समय से रह रहे सुरेंद्र कौल ने नयी पीढ़ी को इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'ये रिवाज हमारी आत्मा से जुड़ा है। ये रीति रिवाज हमें हमारी मातृभूमि की याद दिलाते हैं जिसे हम हिंसा और भय के कारण छोड़ आए हैं।' 'टेक्सास कश्मीरी बिरादरी' के अध्यक्ष अमित रैना ने कहा, 'यह अष्टमी सिर्फ परंपरा नहीं है, यह हमारी आस्था है। अपने त्योहारों के माध्यम से हम कश्मीर की संस्कृति को जीवित रखते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि वे कौन हैं। फिर भी घर लौटने की चाह एक ऐसा दर्द है जिसे हम हर दिन सहते हैं। इस दौरान बच्चों ने भजन गाए और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया जो परंपरा के साथ उनके एक मजबूत संबंध को दर्शाता है।

ऑफ बीट

कार्डियो वजन उठाने से पहले करना चाहिए या बाद में?

फिटनेस के प्रति जुनूनी लोग दशकों से इस प्रश्न पर बहस करते रहे हैं कि 'कार्डियो' करना वजन उठाने से पहले बेहतर होता है या बाद में? हाल तक, इसका उत्तर काफी हद तक पसंद पर निर्भर करता था - कुछ लोग वजन उठाने से पहले जॉगिंग करते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि पहले वजन उठाना वसा को खत्म करने के लिए बेहतर है। लेकिन एक नए शोध ने अंततः इस लंबे समय से विवादित प्रश्न का उत्तर दे दिया है। शोध के अनुसार, आपके व्यायाम का क्रम इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि आप कितनी चर्बी कम करते हैं। जिन प्रतिभागियों ने वजन उठाने के बाद कार्डियो किया, उनमें कार्डियो करने के बाद वजन उठाने वालों की तुलना में काफी अधिक चर्बी कम हुई और वे पूरे दिन शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहे। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को 12 सप्ताह के लिए तीन समूहों में विभाजित किया। दोनों व्यायाम समूहों ने एक जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाए, केवल व्यायाम क्रम में अंतर था। प्रतिभागियों ने बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बाइसेप कर्ल और स्क्वाट जैसे व्यायाम किए। कार्डियो सत्र में 30 मिनट तक 'साइकिलिंग' शामिल थी। दोनों समूहों के प्रतिभागियों ने अपनी हृदय संबंधी फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक बनावट में सुधार का अनुभव किया।

X ट्रेंड f

भारत-साइप्रस संबंध

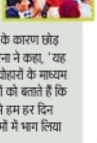

साइप्रस हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के विशेष सम्मान के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस का आभार। यह यात्रा भारत-साइप्रस संबंधों को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भूमिपुत्रों का अधिकार

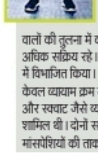

कांग्रेस चाहती थी कि राष्ट्र की संपत्ति पर एक विशेष समुदाय का अधिकार हो। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धांत है कि राष्ट्र की संपत्ति पर सबका अधिकार हो, लेकिन सर्वप्रथम उसका हक भूमिपुत्रों का होना चाहिए।

-हिमंत बिस्व शर्मा, सीएम, असम

विदेश नीति में खामियां

अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी विदेश नीति में खामियां है। शायद, प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने विदेश मंत्री की बार-बार की गई गलतियों पर विचार करना चाहिए और कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए।

- मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

मृतकों को श्रद्धांजलि

केदारनाथ में हेलिकॉप्टर क्रैश के मृतकों को श्रद्धांजलि एवं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार सुनिश्चित करे कि सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे बिना कोई भी उड़ान न भरी जाए।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

डिजिटल क्रांति

सबका सशक्तीकरण

भारत में डिजिटल क्रांति हर नागरिक का सशक्तीकरण कर उसे टूल्स, पहुंच व अवसरों के मामले में आगे बढ़ा रही है। पिछले 11 साल में भारत एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन से गुजरा है जिसने प्रशासन को पुनः परिभाषित कर नागरिकों का सशक्तीकरण किया तथा देश की विकास यात्रा को निर्देशित किया है। दूरदर्शी नेतृत्व से संचालित तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति से सशक्त तकनीकी खोज एवं जन-सहभागिता ने भारत की डिजिटल क्रांति को शहरी सीमाओं से दूर ले जाकर देश के कोने-कोने तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार एक समय अलंघ्य समझी जाने वाली डिजिटल बाधा को दूर किया गया है। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने हाल ही में कहा था कि इस परिवर्तन से न केवल करोड़ों लोगों को जोड़ा गया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि तकनीक हर नागरिक तक पहुंचे। आज प्रशासन पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी और सक्षम है। 'रियलटाइम डैशबोर्ड', 'डेटा इंटीग्रेशन' एवं डिजिटल ढांचे ने जवाबदेही का स्तर बढ़ाया है तथा कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सरकार की अनेक प्रमुख योजनाओं ने खासकर ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है। इनमें 'डिजीलाकर', 'कोविन', 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन', 'यू-विन' तथा 'ई-संजीवनी' करोड़ों लोगों के लिए जीवनरेखा बन गई हैं। ये प्लेटफार्म केवल डिजिटल टूल न होकर आम नागरिकों के लिए संसाधनों तक पहुंच, सशक्तीकरण और गरिमा का स्रोत बन गए हैं।

डिजिटल क्रांति का एक सर्वाधिक प्रशंसनीय चेहरा 'यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस'-यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतानों में वृद्धि है। सरकार भविष्य के लिए तैयार 'आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस'-एआई जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही है। सर्वोच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में तीन एआई एक्सलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही अनेक स्वदेशी एआई माडलों, जैसे 'भारतजेन', 'सर्वम-1' तथा 'हनुमान एवरेस्ट-1' का विकास किया जा रहा है जो भारत को वैश्विक एआई दौड़ में अग्रणी स्थान प्रदान करेंगे। 'भारतनेट' परियोजना के अंतर्गत 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है तथा देश भर में 8.9 लाख किलोमीटर से अधिक आप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं। भारत दुनिया का सर्वाधिक सस्ता मोबाइल डेटा प्रदान करता है जिससे डिजिटल समावेशन स्तरीय होता जा रहा है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के साथ ही सच्चे 'डिजिटल इंडिया' की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। डिजिटल ढांचे के व्यापक विस्तार के बावजूद जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा अब भी डिजिटल साक्षरता से संघर्ष कर रहा है। बहुत से लोग, खासकर ग्रामीण और संकटग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावी रूप से डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रयोग में कुशल नहीं हैं। डिजिटल समझदारी में यह कमी तकनीकी प्रगति के लाभ जनता तक पहुंचाने में बाधा बनती है। इसके साथ ही डिजिटल गतिविधियों में तेजी से साइबर सुरक्षा और डेटा की निजता के बारे में गंभीर चिन्तायें पैदा होती हैं। डिजिटल लेनदेन तथा डेटा का प्रयोग बढ़ने के साथ ही मजबूत विधिक ढांचों, जीवन्त साइबर सुरक्षा प्रणालियों और व्यापक सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल इकोसिस्टम में विश्वास पैदा किया जा सके। कुछ सुदूर व भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में ढांचागत कमियां भी सामने आ रही हैं जहां बिजली की अनियमित सप्लाई तथा कनेक्टिविटी सुनिश्चित न होना बड़ी बाधायें हैं। भारत के सामने वर्तमान समय में 'डिजिटल क्रांति' के प्रसार पर और जोर देते हुए उसे ज्यादा समावेशी, सुरक्षित तथा समतापूर्ण बनाने की चुनौती है। भारत वर्तमान समय में '2047 तक विकसित भारत' के दृष्टिकोण पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में डिजिटल लहर हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। इससे 'डिजिटल क्रांति' के माध्यम से हर नागरिक को आगे लाने, उसे टूल्स के माध्यम से सशक्त बनाने तथा उसके सामने पहुंच और अवसरों में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जेल में बंद आंग सान सूकी

एक समय दुनिया भर में लोकतंत्र का प्रतीक मानी जाने वाली म्यांमार की 80 वर्षीय जेल में बंद आंग सान सूकी की पीड़ा पर दुनिया भर में गुस्सा नहीं पैदा हो रहा है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

आंग सान सूकी 19 जून, 2025 को अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर 81वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। पिछली अंतिम फर्जी सुनवाई 30 दिसंबर, 2022 को हुई थी जिसकी दुनिया भर में व्यापक निन्दा हुई थी। इसमें उनको सात साल के लिए जेल भेज दिया गया था। इसके साथ सूकी को 33 साल कैद की सजा दी गई है जिसे बाद में घटा कर 27 साल किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि म्यांमार के सैनिक शासक जो स्वयं को 'राज्य प्रशासनिक परिषद' कहते हैं, चाहते हैं कि वे जेल में ही मर जाएं। इस संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी लोकतंत्रों में उनके जेल में बंद होने तथा म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के प्रति दिलचस्पी घटती जा रही है। हालांकि, असंदिग्ध रूप से उन्होंने सैनिक शासन का समर्थन नहीं किया है और उसके तथा उसके नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

इसके बावजूद उनके लगातार जेल में बंद होने तथा सैनिक शासन द्वारा नागरिकों के खिलाफ बर्बर सैनिक कार्रवाई के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति बहुत कम और हल्की हो गई है। यह बर्बर सैनिक दमन पीपुल्स डिफेंस फोर्स-पीडीएफ, विपक्षी राष्ट्रीय एकीकरण सरकार-एनयूजी तथा नस्ली सशस्त्र संगठनों-ईएओ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हो रहा है जो एक दूसरे से सहयोग कर सैनिक शासक के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं।

हालांकि, इसका कारण यह भी है कि यूक्रेन युद्ध तथा गाजा में इस्राइली कार्रवाई जैसेस नए मुद्दे सामने आ गए हैं और उनको अब सामान्य वैश्विक विमर्शों में केन्द्रीय स्थान मिल रहा है। लेकिन वैश्विक आकर्षण में कमी के कारण सैनिक शासक पर देश में लोकतंत्र बहाली के लिए दबाव घटाने में सहायता मिली है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि सैनिक शासक को तभी सत्ता से हटाया जा सकता है जब उसे म्यांमार में इस समय जारी गृह युद्ध में पराजित कर दिया जाए।

सैनिक शासक के खिलाफ संघर्षरत बलों में पीडीएफ के अलावा थ्री ब्रदरहुड एलायंस भी है जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी-एमएनडीएए उत्तरी शान राज्य के कोकांग विशेष क्षे9 में सक्रिय है, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी-टीएनएलए शान राज्य में तथा अराकान आर्मी-एए देश के पश्चिमी हिस्से के राखीन राज्य में सक्रिय हैं। ये पीडीएफ व अन्य नस्ली सेनाओं के साथ सहयोग कर सैनिक शासक के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। धीरे-धीरे ये बल सरकारी बलों पर हावी होते जा रहे हैं। म्यांमार की सेना 'सिट-टैट' एलायंस द्वारा हमलों के बाद कई पराजयों का सामना कर चुकी है। 27 अक्टूबर, 2023 को शुरू किए इस आक्रमण का नाम 'आपरेशन 1027' रखा गया है।

एए ने अप्रैल, 2024 के बाद पूरे राखीन प्रांत पर कब्जा कर लिया है। एमएनडीएए ने 31 जुलाई, 2024 को दावा किया था कि उसने सिट-टैट के लाशियो सैनिक अड्डे और चीनी सीमा के निकट शान राज्य के हवाईअड्डे पर कब्जा कर लिया है। यह सैनिक शासक के लिए बड़ा झटका था। विवेक शंकर ने 5 अगस्त, 2024 को 'द न्यूयार्क टाइम्स' में दावा किया था कि 'लाशियो शहर और उसके हवाईअड्डे पर कब्जा हो गया है। यहां करोड़ों डालर खर्च कर हाईस्पीड नेल नेटवर्क व अन्य ढांचागत परियोजनायें सीमा के दोनों ओर बनाई गई थीं।' विपक्षी बलों ने अब म्यांमार की सीमाओं और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और सेना का नियंत्रण केन्द्रीय इरावडी घाटी के प्रमुख शहरों तथा जमीनों पर ही कब्जा है। सेना अब शहरों और कस्बों में भी हार रही है। 13 अगस्त, 2024 को 'द इरावडी' वेबसाइट में दावा किया गया था कि 'सैनिक शासक का कब्जा अब म्यांमार के 350 शहरों में से केवल 100 पर बचा है।'

इसमें रक्षा मंत्री यू यी मोन के हवाले से कहा गया था कि म्यांमार के 350 कस्बों में से केवल 98 पर ही सेना का कब्जा बचा है। एनयूजी के रक्षा मंत्रालय ने म्यांमार के कस्बों को चार श्रेणियों में बांटा है। इनमें से 75 पर पूरी तरह सरकार-विरोधी समूहों का कब्जा है, 105 ने सरकार-विरोधी समूहों के समक्ष समर्पण कर दिया है, 75 में संघर्ष चल रहा है तथा केवल 98 कस्बे ही सरकार के नियंत्रण में बचे हैं।

4 जून, 2025 को द इरावडी में बेनयार आंग के लेख में दावा किया गया था कि नस्ली अराकान आर्मी-एए ने नवंबर, 2023 में राखीन आक्रमण शुरू करने के बाद पश्चिमी राज्य के 17 कस्बों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। सैनिक शासक के नियंत्रण वाले तीन कस्बों में से सिटवे व कायुकफू में लड़ाई जारी है तथा मानुंग ऐसा अकेला कस्बा बचा है जहां से टकराव की खबर नहीं है। एए ने भारत और बांग्लादेश सीमा से सटे पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले उसने नाफ नदी से सटे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जिसमें मुंगडा, बूठीडौंग और चिन राज्य के पलेटवा कस्बे भी शामिल हैं। इससे बांग्लादेश से उसका सीधा संबंध स्थापित हो गया है तथा भारत मिजोरम सरकार के माध्यम से उनसे सपर्क बनाए हुए है। असंदिग्ध रूप से सरकारी सेना ने जवाबी हमला करने का प्रयास किया है। 19 मार्च, 2025 को द इरावडी में प्रकाशित लेख 'मैपिंग द म्यांमार जुंटाज गेन्स, लासेज एंड स्टेलमेट्स सिंस 1027' में सैनिक विश्लेषक ने लिखा था कि 2024 में सैनिक शासक की सेना सिट-टैट ने ज्यादा गतिशील रणनीति अपनाते हुए मोबाइल व सक्रिय रक्षात्मक रणनीतियां अपनाई और पूरे देश में जवाबी हमले किए।

उसकी निर्भरता मुख्यतः युद्धक विमानों तथा ड्रोनों पर थी। लेकिन इन रणनीतियों के कारण सार्थक या निर्णायक विजय नहीं प्राप्त हुई। लेख में बताया गया है कि सैनिक शासक द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र कुल मिला कर उन कस्बों और शिविरों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं हैं जिन पर प्रतिरोधी बलों ने पहले कब्जा किया था। इसके अलावा सैनिक शासक के पुनः कब्जे वाले क्षेत्रों पर लगातार खतरा मंडरा रहा हैऔर उनको प्रतिरोधी बलों ने घेर रखा है।

लेख में यह भी कहा गया है कि विपक्षी बलों ने गुरिल्ला शैली की कार्रवाइयां तेज की हैं जिनमें घात लगा कर हमले करना, माइन्स बिछाना तथा सिट-टैट के ठिकानों पर लगातार हमले शामिल हैं। असंदिग्ध रूप से उनको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, सैनिक शासक ने 2024 में अधिकांश लोईका कस्बे के बड़े हिस्सों पर पुनः कब्जा कर लिया था और करेनी प्रतिरोधी बलों को पीछे हटना पड़ा था। संभवतः इसका कारण उनके पास गोला-बारूद की कमी थी।

लेकिन सिट-टैट को अपनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और दीर्घकालीन रूप से उसे निश्चित रूप से पराजय साफ दिख रही है। उसमें उत्साह का घोर अभाव है तथा आंतरिक मतभेद बढ़ रहे हैं। अनेक तीन-सितारा जनरलों को हटा दिया गया है। अनेक युवा अधिकारी असंतुष्ट हैं क्योंकि उनकी पहचान पूरे देश के दुश्मन की तरह हो रही है। 'युनाइटेड इंस्टीट्यूट आफ पीस' में 4 मई, 2023 को प्रकाशित एक लेख के अनुसार, 'सिट-टैट की जो शक्ति विद्रोह के पहले 300,000-400,000 थी अब वह घट कर लगभग 150,000 कर्मियों की बची है।'

हालांकि, सिट-टैट को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में लाभ प्राप्त है, पर इस तथ्य के कारण उसे इनका ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घने जंगलों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में इनका प्रयोग बहुत कठिन है जहां गहरी खाइयां और खड़ी ढलाने हैं। इन पर सैनिक शासक विरोधी बलों का कब्जा है। वैसे भी तोपखाने और वायुसेना के समर्थन से युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं, जब उनका मुकाबला अच्छी तरह हथियारों से लैस और प्रशिक्षित सैनिकों से हो। यदि ऐसा न होता तो अमेरिका की वियतनाम में विजय होती। अब सैनिक शासक को सत्ता से हटाने के लिए केवल समय की प्रतीक्षा है। जब ऐसा होगा तो म्यांमार में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की विजय होगी। यह आंग सान सूकी द्वारा छेड़े गए लंबे संघर्ष की विजय होगी।

लेकिन फिलहाल सूकी पर बहुत गंभीर खतरा मंडरा रहा है और उसके बारे में बात होनी चाहिए। सैनिक शासक जेल में जहर देकर उनकी हत्या करा सकते हैं अथवा उनकी मौत को वृद्धावस्था संबंधी प्राकृतिक कारणों से हुआ बताया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसका कारण सैनिक शासक का यह विश्वास होगा कि पश्चिम की म्यांमार में दिलचस्पी समाप्त हो गई है और वह ज्यादा महत्वपूर्ण दिखने वाले मुद्दों के बहाने म्यांमार में सैनिक शासन के दमन तथा लोकतंत्र की हत्या की रूटीन निन्दा के सिवा और कुछ नहीं कर रहा है।

क्या सीएम पद का चेहरा बनेंगे चिराग

> भाजपा के पास वर्तमान में बिहार के मतदाताओं के सामने पेश करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर से एक आकर्षक सीएम उम्मीदवार का अभाव है।

विवेक अवस्थी
(लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं)

युवा, गतिशील और अक्सर पीएम मोदी के हनुमान के रूप में संदर्भित, चिराग पासवान बिहार के लिए भाजपा के संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं। भाजपा के पास वर्तमान में बिहार के मतदाताओं के सामने पेश करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर से एक आकर्षक सीएम उम्मीदवार का अभाव है। सुशील मोदी के निधन के बाद, यह शून्य को भरने में विफल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें 7.64 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के साथ 245 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, नवंबर 2025 तक होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे राजनीतिक माहौल बदलना शुरू होता है, भाजपा चिराग पासवान को राज्य का नेतृत्व करने के लिए एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, ने लगातार राजनीतिक पुनर्संयोजन के लिए ख्याति प्राप्त की है। उनकी पिछली साझेदारियां, खासकर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री रहने के बाद, उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी ने मतदाताओं और उनके सहयोगियों दोनों के बीच विश्वास की कमी पैदा कर दी है।

हालांकि भाजपा व्यावहारिक कारणों से नीतीश कुमार के साथ बनी हुई है, लेकिन पार्टी उनके अप्रत्याशित राजनीतिक पैंतरेबाजी से असहज रहने के लिए जानी जाती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास नीतीश के प्रतिद्वंद्वी के समान व्यापक अपील नहीं होने के कारण, भाजपा को एक करिश्माई, युवा-प्रेरित नेता की तत्काल आवश्यकता है जो इस अंतर को पाट सके और चिराग पासवान इस बिल में फिट बैठते हैं। चिराग पासवान युवा ऊर्जा, मृदुभाषी करिश्मा और साफ छवि का अनूठा मिश्रण लेकर आते हैं। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे, वे लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के एक अलग समूह का नेतृत्व करते उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है: अपने गृह राज्य में एक बड़ी, अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाना। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, भाजपा आलाकमान और चिराग पासवान के बीच दो प्राथमिक परिदृश्यों पर चर्चा चल रही है= चिराग अपनी पार्टी लोजपा (रामविलास) का भाजपा में विलय कर देते हैं और आधिकारिक तौर पर बिहार के लिए पार्टी के सीएम उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं। यह विकल्प संभवतः चिराग को अधिक राजनीतिक स्थिरता और अधिकार प्रदान करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें भाजपा में पूरी तरह से एकीकृत होना होगा, जिसका उनके कुछ पार्टी सहयोगी विरोध कर सकते हैं। चिराग एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, उन्हें सीएम चेहरे के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि, यह रास्ता चुनौतियों से भरा है-मुख्य रूप से सीट-बंटवारे की दुविधा। प्रमुख भागीदार के रूप में, भाजपा निर्वाचन क्षेत्रों और मंत्रिस्तरीय विभागों का एक बड़ा हिस्सा मांगेगी, जो संभावित रूप से भविष्य की गठबंधन सरकार में चिराग के प्रभाव को सीमित कर सकती है। शीर्ष पद पर चिराग की संभावित पदोन्नति भाजपा के लिए कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है।

इससे पार्टी को बिहार में अपने नेतृत्व को तरोताजा करने, नीतीश कुमार के घटते प्रभाव से पैदा हुए खालीपन को भरने और दलित वोट बैंक को साधने का मौका मिलेगा, जो परंपरागत रूप से उनके पिता रामविलास पासवान के प्रति वफादार रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी रास्ते को अपनाने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी बढ़ती बेचैनी और बिहार की राजनीति में बढ़ता दबदबा संकेत देता है कि बदलाव आसन्न है। विलय, हालांकि जटिल है, लेकिन यह उन्हें बिहार के शासन में गहरी जड़ों के साथ एक दीर्घकालिक राजनीतिक भविष्य प्रदान कर सकता है। 2020 के बिहार चुनावों में, लोजपा सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रही और इसके नौ उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे।

पिछले आम चुनावों में चिराग पासवान की लोजपा को पांच सीटें मिली थीं। संक्षेप में, लोजपा का भाजपा में विलय दोनों दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि चिराग के उम्मीदवारों को भाजपा के नाम पर उच्च जाति के वोटों का उचित हिस्सा मिलेगा जैसे-जैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह सवाल बड़ा हो रहा है= क्या चिराग पासवान भाजपा के नए बिहार का चेहरा बनेंगे?

आप की बात

इस्राइल-ईरान युद्ध

इस्राइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न केवल पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा रहा है, बल्कि यह वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। ईरान लंबे समय से इजरायल के अस्तित्व को चुनौती देता रहा है और इजरायल ने इस खतरे को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही इस पर चिंता जताएं, लेकिन उनकी नीतियां इजरायल के पक्ष में ही दिखाई देती हैं। इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी है। विश्व पहले ही यूक्रेन-रूस युद्ध से त्रस्त है। अब यह नया युद्ध दुनिया भर में महंगाई, ऊर्जा संकट और कूटनीतिक अस्थिरता को गहरा करेगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह परिस्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। भारत को इस समय किसी भी ध्रुवीकरण से बचते हुए रणनीतिक मध्य मार्ग अपनाना होगा। भारत को अपने आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करने के साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भी प्राथमिकता देनी है। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने मोदी को फोन कर उनका समर्थन मांगा है। इससे विश्व राजनीति में मोदी का महत्वपूर्ण कद स्पष्ट होता है, लेकिन इससे विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की चुनौती और गंभीर हो जाती है।

–**सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

तानाशाह द्वारा हत्या

तानाशाही शासन पद्धति में मानवाधिकार, न्याय, लोकतंत्र एवं पर्यावरण स्वच्छता का कोई स्थान नहीं है। इनकी बातें करने के कारण किसी की जान भी जा सकती है। दुनिया भर में हर वर्ष इन्हीं कारणों से हजारों लोग मार दिए जाते हैं। तीस साल पहले नाइजीरिया के क्रूर तानाशाह ने पर्यावरणवादी कार्यकर्ता केन सारो विवा को उसके नौ सहयोगियों के साथ फांसी पर लटका दिया था। इतने वर्ष बाद वर्तमान हुकूमत ने उस सजा को गलत बताते हुए दिवंगत कार्यकर्ता को माफ कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को नाइजीरिया के ओगोनीलैंड में तेल बहुराष्ट्रीय कंपनियों, खासकर शैल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए दंड दिया गया था। क्षमादान की घोषणा के साथ ही नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने सारो विवा और उनके साथी प्रचारकों को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया, जिन्हें ओगोनी नाइन के रूप में जाना जाता था। वर्तमान परिदृश्य में यह प्रकरण पर्यावरण संरक्षण और उसके लिए संघर्ष कर रहे पर्यावरण एक्टिविस्टों के प्रति अंतरराष्ट्रीय समर्थन की मांग करता है। विडंबना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी तेल उत्पादक देश पर्यावरण की घोर अनदेखी कर ज्यादा से ज्यादा तेल निकालने को उचित ठहरा रहे हैं।

– **जंग बहादुर सिंह**, जमशेदपुर

ईरान पर हमला

इसराइल ने ईरान पर हमला कर खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव को काफी बढ़ा दिया है। युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है क्योंकि दोनों देशों के पास घातक और अत्याधुनिक हथियारो का जखीरा मौजूद है। यदि दोनों के मध्य तनाव और बढ़ता है तो यह भारत के लिए भी चिंता पैदा कर सकता है। चिंता का प्रमुख कारण भारत के दोनों देशों से काफी अच्छे व्यापारिक और रक्षा संबंध हैं। भारत के करीब एक करोड़ लोग खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं युद्ध की स्थिति में इनकी सुरक्षा की चिंता पैदा हो सकती है। साथ ही भारत में हर वर्ष खाड़ी देशों से करोड़ों-अरबों रूपये इन भारतीयों द्वारा भेजे जाते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सहायक है। आपरेशन सिंदूर के समय हमारे देश का इसराइल ने खुलकर समर्थन किया था और इस कार्रवाई को उचित बताया था। लेकिन ईरान से भी भारत के ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में भारत किसी एक का साथ देने की स्थिति में नहीं है। उसने दोनों देशों से बातचीत व कूटनीतिक माध्यमों से तनाव कम करने का आग्रह किया है। यह सही दृष्टिकोण है। हालांकि, इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ईरान के समर्थन से ही हूती, हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठन फल-फूल रहे हैं।

– **संजय डागा**, इन्दौर

विमान हादसा

अहमदाबाद में विमान हादसे में इतनी जाने चली गई। इससे हर कोई स्तब्ध है। आधुनिकता के इस युग में विश्व ने चाहे जितनी भी उन्नति कर ली हो पर समय चक्र के आगे सभी नतमस्तक हैं। मौत आने में चंद सेकेंड भी नहीं लगाती और लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। कभी किसी ने इस प्रकार की घटना के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुरक्षित विमान सेवा और भारतीय विमान सेवाएं अपना अलग मुकाम रखती हैं। पर न जाने क्या हो गया कि इतना बड़ा हादसा घटित हो गया। जांच के अंतिम परिणाम आने तक सवाल-जवाब में अभी कई उतार-चढ़ाव आयेंगे। लेकिन समय ने सीख दी है कि हर एक धरतीवासी चाहे वह कोई भी हो मौत कब कहां और कैसे आ जाए, यह कोई नहीं कहें सकता है। जीवन में जन्म-मृत्यु की अनहोनी को कोई समझ नहीं सका है। समय बीतने के साथ ही इस त्रासदी का जख्म भर सकता है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रभावितों को उचित मुआवजे के साथ भविष्य में विमान दुर्घटनायें तथा इस के साथ ही हर प्रकार की दुर्घटनायें रोकने के प्रयास होने चाहिए।

– **हरिहर सिंह चौहान**, इन्दौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 102

तेज जांच जरूरी

अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की उड़ान 171 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सबका ध्यान एक बार फिर विमानन कंपनी, नियामक और देश में नागरिक विमानन की व्यापक स्थिति की तरफ चला गया है। यह विमान रनवे से दो किलोमीटर दूर एक मेडिकल हॉस्टल पर जा गिरा। मगर अभी तक यह पता नहीं है कि यह विमान दुर्घटना का शिकार कैसे हुआ। बेहतर यही होगा कि इस विषय में कोई अटकल लगाने के बजाय जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाए। यह भी आवश्यक है कि ये रिपोर्ट प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा पारदर्शी ढंग से तैयार की जाए और इसे समय पर जारी किया जाए। इस जांच की नोडल एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) को बनाया गया है जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की ही शाखा है। भारत ने 2012 में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किया था। इसने जो इकलौती बड़ी जांच की वह थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 1344 के 2020 में कोझिकोड हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त होने की। दुनिया भर में अधिकांश जांचें वैश्विक विशेषज्ञों की सहायता से की जाती हैं, अक्सर इसमें उस देश से भी सहयोग लिया जाता है जहां वह उड़ान जा रही होती है। चूंकि इस मामले में विमान लंदन के गैटविक हवाई अड्डे पर उतरना था और उसमें सवार 50 से अधिक यात्री ब्रिटिश नागरिक थे इसलिए यूनाइटेड किंगडम की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी ने पहले ही चार लोगों को सहायता के लिए नियुक्त कर दिया है। दुर्घटनाग्रस्त विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भी कुछ लोग भेजे हैं।

अभी तक की यह दूसरी ऐसी बड़ी हवाई दुर्घटना है, जिसकी जांच एएआईबी कर रही है। इससे पता चलता है कि विमानन उद्योग के बेहद तेज विस्तार के बावजूद भारत में उड़ान कितनी अधिक सुरक्षित हैं। 1970 और 1980 के दशक में कई विमान देश में हादसों के शिकार हुए और भारतीय विमानन उद्योग आतंकी हमलों समेत तमाम चुनौतियों से जूझता रहा। 21वीं सदी में निजी विमानन कंपनियों का विस्तार हुआ और यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही बड़ी विमान दुर्घटनाओं तथा मौत के मामलों में काफी कमी आई है। देश के विमानन क्षेत्र ने कड़ी मेहनत से अच्छी खासी प्रतिष्ठा अर्जित की है मगर वह तभी बरकरार रह पाएगी, जब इस दुर्घटना की जांच सहज और विश्वसनीय तरीके से हो और विमानन कंपनियों तथा प्राधिकारियों की सिफारिशों को स्वीकार तेजी से उनका क्रियान्वयन किया जाए।

यह बात भी ध्यान देने लायक है एयर इंडिया कई मोर्चों पर मुश्किलों से जूझती रही मगर 1982 में मुंबई में लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त होने के अलावा उसके विमान (आतंकी वारदात को छोड़कर) किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार नहीं हुए। यह रिकॉर्ड दुनिया की कई बड़ी विमानन कंपनियों के जैसा ही है। परंतु इसकी किफायती सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत खराब रहा है। इस बीच देश में निजी विमानन के 30 सालों में किसी बड़ी निजी विमान सेवा को बड़ी दुर्घटना नहीं झेलनी पड़ी है। ये सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे कि एयर इंडिया की सेवाओं का आंतरिक पुनर्गठन होने और उसका निजीकरण होने के बाद सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है या नहीं। इन सवालों के जवाब शायद जांच से निकलें और इसमें पूरा सहयोग करना कंपनी के हित में होगा। अन्य देशों की कुछ घटनाओं मसलन 2016 में इजिप्टएयर की उड़ान 804 जैसे मामलों में जांच में विलंब हुआ, विवाद हुए और राजनीतिक प्रतिबंध देखे गए। भारत में इस जांच में ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार ने 2030 तक देश के भीतर हवाई यातायात दोगुना करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस दौरान 50 और हवाई अड्डे तैयार करने हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे में एएआईबी के काम पर बारीक नजर रखनी होगी और उसे भी जितनी जल्दी संभव हो सके एक व्यापक और सटीक रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

भारत के लिए अनुचित पाकिस्तान से तुलना

अगर भारत को सहयोगी मानने वाली इकलौती महाशक्ति भी इस क्षेत्र को भारत-पाकिस्तान को आमने-सामने रखकर एक चश्मे से देखती है तो यह स्वीकार्य नहीं है। यह बात भारत के प्रभाव को बढ़ाने के बजाय उसे कम करती है।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

किसी खोटे सिक्के की तरह एच शब्द एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गया है। एच यानी हाइफन जो हमें पाकिस्तान के साथ रखता है। इसकी वापसी अवांछित है क्योंकि एक के बाद एक हमारी सरकारों ने दशकों तक मेहनत करके हमें इससे निजात दिलाई थी। एक जमाने में बड़ी शक्तियां (पढ़ें अमेरिका) हमारा और पाकिस्तान का नाम एक साथ लेकर एक तरह की समकक्षता का परिदृश्य तैयार करती थीं। हमने उससे छुटकारा पाया था लेकिन अब वह वापसी करता दिख रहा है। अब तीन चीजें हो सकती हैं।

पहली चीज को हम जीरो-सम गेम कह सकते हैं जहां एक का लाभ और दूसरे की हानि बराबर हों। अगर अमेरिका उपमहाद्वीप को इस तरह देखता है तो उसे इस रिश्ते में संतुलन बनाकर चलना होगा। एक का लाभ दूसरे का नुकसान है। भारत को यह तुलना नापसंद है। वह अपना कद अलग मानता है और पाकिस्तान के साथ तुलना उसकी अवमानना है।

दूसरी बात है 'कद से इनकार।' अपनी बढ़ती व्यापक राष्ट्रीय शक्ति की बदौलत भारत मानता है कि उसे एक प्रभावी स्थान हासिल है। अगर अमेरिका जैसा साझेदार भी इस क्षेत्र को भारत-पाकिस्तान को बराबरी पर रखकर देखेगा तो यह अस्वीकार्य है। यह बात भारत के कद को घटाती है। यह दोहरी मुश्किल है क्योंकि चीन पहले ही भारत के उभार को नकार रहा है। भारत अमेरिका से यही उम्मीद करेगा कि वह उसका समर्थन करे जबकि वह पाकिस्तान को खुश करने वाली बातें कर रहा है। जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि क्वाड के जरिये चीन को नियंत्रित करने में हम साझेदार हैं।

तीसरी बात, इसका अर्थ है 'एम' शब्द की वापसी जो हमें पसंद नहीं। यहां एम शब्द से तात्पर्य मीडिएशन यानी मध्यस्थता से है। भारतीय जनमानस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले दशकों में हुई प्रगति को यह कहकर मिट्टी में मिला दिया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। अब हम जानते हैं कि उनकी रुचि मध्यस्थता में नहीं बल्कि श्रेय लेने में थी। उन्होंने कहा कि कोई उनको श्रेय नहीं दे रहा है जबकि उन्होंने परमाणु युद्ध रुकवाया। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस क्षेत्र में ट्रंप की नई अभिरुचि परमाणु युद्ध के डर से उत्पन्न हुई है। ऐसे में उन्हें लगता है कि वे दुनिया का ध्यान दोबारा परमाणु खतरे की ओर ले आने में कामयाब रहे हैं जबकि भारत ने दशकों की मेहनत से आतंक के खिलाफ वैश्विक साझेदारी का माहौल बनाया था। बिलावल भुट्टो का बयान इसकी बानगी है जिन्होंने अपनी चिरपरिचित अतिरंजित शैली में कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका भारत को कान पकड़कर बातचीत के लिए राजी करेगा। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान ने हताशा में अमेरिका के साथ खोया रिश्ता दोबारा कायम करने में सबकुछ झोंक दिया है। परंतु ट्रंप पर भरोसा करने वालों का अंत हमेशा एक दुखद गीत से हुआ है: 'इक बेवफा से प्यार किया...हाय रे हम ने ये क्या किया।' ट्रंप केवल लेनदेन पर यकीन करते हैं उनकी वफादारी किसी के प्रति नहीं है। वह भी अपने घरेलू समर्थकों को लेकर उतने ही सजग हैं जितने कि भारत में नरेंद्र मोदी।

अच्छी बात यह है कि हमारा नीतिगत प्रतिष्ठान अभी भी भावुक होकर टिप्पणी नहीं कर रहा है और उसने सार्वजनिक रूप से कोई चिंता नहीं दिखाई। वह उस मुद्दे पर काम कर रहा है जो इस वक्त सबसे अहम है यानी भारत-अमेरिका व्यापार समझौता। अगर यह कामयाब रहा तो काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इस बीच किसी ने भी 'के' शब्द का जिक्र नहीं किया है। कोई यह नहीं कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर पर बातचीत करनी चाहिए और यह भी कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि ट्रंप कश्मीर मुद्दे से अवगत भी हैं या नहीं।

कहने का अर्थ यह कि ट्रंप इतिहास, तथ्यों और विचारधारा से परे दुनिया को अपने ही नजरिये से नया स्वरूप देने में लगे हैं। वह नाटो को बेतुका बना रहे हैं, उन्होंने पश्चिमी गठबंधन का मखौल उड़ाया, कनाडा के प्रधानमंत्रियों का लगातार मजाक उड़ाया और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी वह धैर्य का परिचय बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। उन्हें वोलोदीमिर जेलेंस्की नापसंद हैं जबकि व्लादीमिर पुतिन उन्हें पसंद हैं। उनका ताजा बयान देखिए: 'पुतिन कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में उनके 5.1 करोड़ लोग मारे गए और हम साझेदार थे। अब हर कोई रूस से नफरत करता है और उन्हें जर्मनी और जापान से प्यार है। इसे समझाइए। यह दुनिया अजीब है।' यह उम्मीद करना सही नहीं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास की फिक्र किए बिना दुनिया को अपने नजरिये से बदलने की कोशिश कर रहा है वह पाकिस्तान के साथ अपना जिक्र न किए जाने की हमारी चिंता को समझेगा।

मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के शोरगुल की अनदेखी करके सही किया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री पद के लिए नामित पॉल कपूर ने अपनी नियुक्ति वाली समिति के समक्ष जो बयान दिया है वह परिपक्व और भारत के लिहाज से बेहतर है। लेकिन उनकी एक पंक्ति ने भारत में अनेक लोगों को नाराज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां अमेरिकी हितों के लिए जरूरी होगा वह पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं।

सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंक के विरुद्ध एक जबरदस्त सहयोगी बताया है। यह बयान पेंटागन के एक जरूरी भू-सामरिक विभाजन से आता है जिसके तहत सेंटकॉम पाकिस्तान और भारत दोनों को पैसिफिक कमांड के तहत मानता है।

अपराध कवर करने वाले पत्रकार आपको बताएं कि किसी भी थाना प्रभारी की पहली कोशिश होती है कि उसके थाना क्षेत्र में अपराध कम हों भले ही इसके लिए उसे बुरे से बुरे व्यक्ति से सौदेबाजी करनी पड़ी। पैसिफिक कमांड के मुखिया से आपको एक अलग जवाब मिल सकता है। इससे बढ़कर अफवाहें फैलाने वाले हमारे खबरिया चैनलों ने खुद यह कहानी गढ़ ली कि पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल बने सेनाध्यक्ष को अमेरिकी आर्मी डे परेड के लिए आमंत्रित किया गया है। वो तो व्हाइट हाउस ने खंडन किया कि ऐसे किसी अतिथि को नहीं बुलाया जा रहा है।

आखिर में, हम यह देख सकते हैं कि हमारे संकट में विदेशी संबद्धता का क्या अर्थ हुआ है। इससे हमें मध्यस्थता, हस्तक्षेप और संबद्धता के बीच फर्क करने में मदद मिलेगी। शीतयुद्ध के पश्चात भारत को मानवाधिकार के मुद्दे पर चार सालों तक अमेरिका का जबरदस्त दबाव झेलना पड़ा। परंतु सुधारों के बाद जैसे-जैसे भारत का आर्थिक विकास हुआ, उसका कद भी बढ़ा। 1998 तक समीकरण बदलने लगे थे। क्लिंटन ने अपने दूसरे कार्यकाल में परमाणु हथियार संपन्न भारत की हकीकत को स्वीकार किया। 1999 में उसने करगिल संकट के दौरान अत्यधिक रचनात्मक भूमिका निभाई। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ की खिंचाई ही नहीं कि बल्कि उन्हें 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करगिल से पीछे हटकर अपनी इज्जत बचाने का अवसर भी दिया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अमेरिका के बारंबार हस्तक्षेप और ने दोनों पक्षों को शांत रहने में मदद की। 26/11 के हमले के बाद आतंक से लड़ाई में एकजुटता और उसके बाद की साझेदारी ने दो उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की: पहला, भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रखना बंद किया गया और दूसरा पाकिस्तान के सीने पर 'आतंकी देश' का बिल्ला चिपका रहा।

परंतु वक्त बदलता है। ट्रंप की वापसी के बाद भी वह बदला। इस उपमहाद्वीप में हर संकट को हल करने में अमेरिका की भूमिका रही। ट्रंप ने केवल भाषा बदली वह पुरानी कूटनीतिक भाषा के बजाय पांच साल के बच्चे की तरह श्रेय चाहते हैं। यही नई हकीकत है। खासकर अमेरिका के दोस्तों और साझेदारों के लिए।

उपसंहार- 2001 में जब परवेज मुशर्रफ आगरा शिखर बैठक के लिए आए थे तब वाजपेयी ने नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में उनके लिए दोपहर भोज रखा था। वह इतने चतुर थे कि उन्होंने उसमें फारुख अब्दुल्ला को भी बुलाया और उन्हें मुशर्रफ से एक टेबल की दूरी पर ही बिठाया। तय योजना के मुताबिक मीठा खाते वक्त फारुख उठकर एक बड़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ मुशर्रफ के पास गए और बोले, 'अरे ये देखिए, ये तो तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हो गया।' वहां मौजूद हर शख्स हंस पड़ा।

भाषा आधारित स्ट्रीमिंग कारोबार के नए दावेदार

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

'एकेन बाबू' की शक्ल-सूरत देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक जासूस हैं। मोटे कद-काठी और कम बालों वाले इस किरदार का सृजन 1991 में दिवंगत लेखक सुजन दासगुप्ता ने बांग्ला पत्रिका 'आनंद मेला' के लिए किया था। वर्ष 2018 में 'एकेन बाबू' बांग्ला वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस होइचोई पर एक वेब सीरीज के रूप में सामने आई। यह शो अब अपने 8वें सीजन का सफर तय कर रहा है। एकेन बाबू की लोकप्रियता से उत्साहित होकर होइचोई की मूल कंपनी एसवीएफस एंटरटेनमेंट (कोलकाता स्थित एक बड़ी स्टूडियो एवं वितरक कंपनी) ने एकेन बाबू के किरदार को केंद्र में रखकर 2022 में एक फिल्म का निर्माण किया। इस साल मई में इस सीरीज की तीसरी किस्त 'एकेनः बनारस-ए- विभीषिका' प्रदर्शित हुई। होइचोई एक सब्स्क्रिप्शन आधारित सेवा है जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। यह स्ट्रीमिंग सर्विस 100 करोड़ रुपये राजस्व (वित्त वर्ष 2024-25) के साथ अब थोड़ा मुनाफा कमाने लगी है।

हैदराबाद में तेलुगु स्ट्रीमिंग ऐप' अहा'इस साल 150 करोड़ रुपये राजस्व के साथ नफा न नुकसान की स्थिति में आ जाएगी।' अहा'की शुरुआत माई होम ग्रुप और अल्लू अरविंद की गीता आर्ट्स ने की है। इसके 25 लाख उपभोक्ता (सब्सक्राइबर) हैं।'स्टेज'नाम के की अन्य ओटीटी ने हाल में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं जिनका इस्तेमाल वह अपने उपभोक्ताओं की संख्या मौजूद 44 लाख से बढ़ाकर 7-8 करोड़ करने में इस्तेमाल करेगी। 'स्टेज ' ओटीटी हरियाणवी, भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं में कार्यक्रम की पेशकश करती है और आगे वह मैथिली, बुंदेली, अवधी और मराठी सहित 18 अन्य भाषाओं में भी कार्यक्रम शुरू करना चाहती है।

ये आंकड़े छोटे लगते हैं। मीडिया पार्टनर्स एशिया के अनुसार वर्ष 2024 में स्ट्रीमिंग वीडियो ने विज्ञापन और 12.5 करोड़ उपभोक्ताओं से भुगतान राजस्व के माध्यम से 35,600 करोड़ रुपये जुटाए। इस तरह, कुछ लाख उपभोक्ता और कुछ करोड़ रुपये राजस्व बहुत अधिक प्रतीत नहीं होते हैं। यह स्थिति के पीछे इतिहास और मुनाफा कमाने की संभावना ये दो कारण हैं।

पहले इतिहास पर बात करते हैं। स्ट्रीमिंग भी टेलीविजन की तरह ही कारोबार विस्तार की राह पर चल रही है। भारत में निजी टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 1991 में हुई थी जब स्टार टीवी और सीएनएन ने कदम रखा था। जी 1992 में इस होड़ में शामिल हुआ और इसके तुरंत बाद पहला कलानिधि मारन का सन टीवी (तमिल भाषा का चैनल) 1993 में आया। रामोजी राव के चैनल इनाडु टीवी (तेलुगु) की शुरुआत 1995 में हुई। जी मराठी, एशियानेट (मलयालम), मां टीवी (तेलुगु) और कई अन्य निजी टेलीविजन चैनलों की शुरुआत हुई। जी को छोड़कर कोई भी बड़ी प्रसारण कंपनी गैर-हिंदी भाषा खंड में तत्काल नहीं उतरी।

इसका कारण यह है कि मूल्य एवं कारोबार दोनों के लिहाजसे हिंदी मीडिया एवं मनोरंजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका कारण यह है कि देश के एक बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है। इस भाषा के कार्यक्रमों का तंत्र एवं ढांचा सिनेमा और दूरदर्शन के कारण अच्छी तरह विकसित हो पाया। फिल्म निर्माताओं ने 1980 के दशक में 'बुनियाद' या 'कथासागर' सहित अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम बनाए। हिंदी के बाद तेलुगु और मलयालम दो अन्य ऐसी भाषाएं थीं जिनका ढांचा काफी विकसित था। इन दोनों भाषाओं के लेखक, फिल्म निर्माता, तकनीशियन टेलीविजन पर नए दर्शकों के लिए कार्यक्रम तैयार कर सकते थे। इस तरह, हिंदी के बाद इन भाषाओं ने रफ्तार पकड़ी।

तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं की पहुंच इस कारण से सीमित रही कि हिंदी बोलने वाली आबादी में केवल 5-10 प्रतिशत लोग ही ये भाषाएं बोल सकते हैं। मगर दिलचस्प बात है कि विभिन्न भाषाओं के दर्शकों में दशकों तक सन टीवी भारत में सबसे अधिक देखा जाना वाला चैनल रहा। कोविड-19 महामारी के बाद दंगल टीवी ने इसकी जगह हथिया ली। सन, मां टीवी और कई अन्य चैनल भारत में 10 सर्वाधिक देखे जाने वाले टीवी चैनलों में नियमित रूप से शुमार रहते हैं। इसका कारण यह है कि कई उत्तरी राज्यों में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) की तरह कभी भी केबल टीवी की 80-90 प्रतिशत पहुंच नहीं हो पाई। टेलीविजन पर ये तीनों भाषाएं अपने लगभग सभी दर्शकों तक पहुंच रही हैं मगर हिंदी ऐसा नहीं कर पा रही है।

अन्य भाषाओं की बात करें तो पंजाबी, भोजपुरी, बांग्ला या मराठी बोलने वाले दर्शक द्विभाषी होते हैं। हिंदी ने अपने दमदार कार्यक्रमों की बदौलत इन भाषाओं के बाजार में आसानी से जगह बना लेती है। हिंदी की बराबरी करने का मतलब है लागत में इजाफा करना, जो प्रति एपिसोड 1 लाख रुपये से बढ़कर 10-15 लाख तक पहुंच सकती है। इन बाजारों में विज्ञापन एवं भुगतान राजस्व इतनी अधिक लागत के लिए नाकाफी हैं। इससे साबित हो जाता है कि इन भाषाओं में स्वतंत्र और बड़े दोनों नेटवर्क के प्रयास सफल नहीं हुए जबकि दक्षिण भारतीय भाषाओं में निवेश के सकारात्मक परिणाम मिले। स्टार, वायकॉम18 और जी पंजाबी और गुजराती सहित अन्य भाषाओं में जरूर उतरी मगर उसे सीमित सफलता ही मिली।

यह स्थिति हमें दूसरे कारण की तरफ खींचती है कि क्यों' होइचोई'या' अहा'की धीमी लेकिन निरंतर प्रगति दिलचस्प है। ये दोनों ही मुनाफा देने वाले कारोबार में और उस स्तर पर हैं जहां तक कोई गैर-हिंदी भाषा कारोबार हो सकता है। उनके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि वे एक बड़ी इकाई का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए होइचोई की मूल कंपनी एसवीएफ बांग्ला सिनेमा एवं टेलीविजन पर पिछले 30 वर्षों से केंद्रित रही है। इसका प्रदर्शन उसी तरह रहा है जैसा सन टीवी का तमिल या तेलुगु में इनाडु का रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। 2025 में नेटफ्लिक्स पर भारत से 26 शो एवं फिल्ममौजूद हैं जबकि होइचोई पर 25 शो तो केवल बांग्ला भाषा के हैं।

नई शताब्दी की शुरुआत में कई बड़े प्रसारणकर्ताओं ने स्थानीय कारोबारी इकाइयों का अधिग्रहण कर अपने कारोबार का विस्तार कर लिया। स्टार ने एशियानेट (2009) और मां टीवी (2015) दोनों को खरीद लिया। इस समय ज्यादातर प्रसारणकर्ताओं के कुल राजस्व में गैर-हिंदी भाषाओं के कार्यक्रमों की हिस्सेदारी लगभग 25-30 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अगर भाषा आधारित टेलीविजन का विकास कोई संकेत है तो भविष्य में जब बड़े प्लेटफॉर्म राजस्व जुटाने और अपने गैर-हिंदी कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनकी 'होइचोई' और 'अहा' जैसे ब्रांड खरीदने में काफी दिलचस्पी हो सकती है। अक्सर कहा जाता कि इतिहास स्वयं को दोहराता है।

आपका पक्ष

परिवहन सुविधाएं: विकास की रीढ़

भारत की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। राजमार्गों का विस्तार, गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और आधुनिक रेल नेटवर्क के विकास ने देश की गति और दिशा दोनों बदली है। इन प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय एकता पर पड़ा है। विशेष रूप से रेल परिवहन क्षेत्र में वंदेभारत एक्सप्रेस जैसी उच्च गति की ट्रेनों के परिचालन, कटरा से श्रीनगर तक रेल सेवा का विस्तार और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क का जुड़ना ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। चिनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत की तकनीकी क्षमता और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। यह केवल इंजीनियरिंग की सफलता नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परिवहन परियोजनाओं ने न केवल आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हालांकि, मेट्रो जैसी महंगी परियोजनाओं के बजाय यदि मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ने वाली रेल सेवाओं में तेजी से विस्तार किया जाए, तो यह विकास को और भी व्यापक आधार देगा। परिवहन सुविधाएं केवल सुविधा नहीं, बल्कि विकास का इंजन हैं। इनका समावेशी और संतुलित विस्तार भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

प्रधानमंत्री ने बीते दिनों कटरा स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, यह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच पहली ट्रेन सेवा है

क्या कृषि आतंकवाद करना चाह रहा है चीन

मंगलवार को अमेरिका में राउंडवर्म की तस्करी के आरोप में चीनी विज्ञानी को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में बीते हफ्ते ऐसा दूसरी बार हुआ कि किसी चीनी नागरिक के पास से संदिग्ध जैविक वस्तु मिली है इसके पूर्व चीनी नागरिकों के पास से फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम नामक खतरनाक फंगस मिली थी यह घटना एक नए खतरे की ओर इशारा करती है जिसे कृषि आतंकवाद कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने के लिए शत्रुदेश इस तरह के हथकंडे अपनाता है। चीनी नागरिकों के पास से बरामद राउंडवॉर्म एक प्रकार से , सूक्ष्म से लेकर कई इंच लंबे ये कीड़े होते हैं जो इंसानों और जानवरों की आंतों या ऊतकों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते है इसी प्रकार फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम नामक खतरनाक फंगस का उपयोग किसी कृषि आधिरत अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को गंभीर रूप से अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। इस फंगस से 'हेड ब्लाइट' नामक बीमारी होती है, जिससे गेहूं, जौ, मक्का और चावल की फसलें बरबाद हो जाती है। यह जानवरों और इंसानों में भी गंभीर बीमारी की वजह बन सकती है। चीन का भारत विरोधी रुख सर्वज्ञात है अतः भारत को अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। भारत को एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ानी होगी ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस या वायरस यहां पहुंचकर कोई गंभीर समस्या पैदा न कर दे।

विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

फ्रांस के तीन दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में रणनीतिक समुदाय के साथ चल रहे वैश्विक पुनर्संतुलन और मजबूत भारत-यूरोप साझेदारी के वादों पर विमर्श किया।

कल्पमेधा

बिना चिंतन का अध्ययन तो परिश्रम नष्ट करता है, बिना शिक्षा प्राप्त किए विचार करना भयावह है।

– कन्फ्यूशियस

प्रक्षेपण के खतरे

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग विकास की राह पर है। साथ ही, ओजोन परत का क्षरण वर्तमान समय की सबसे प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं में से एक बन गया है। ओजोन परत क्षरण ने पराबैंगनी विकिरण के जोखिम में वृद्धि और स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पर इसके प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। ओजोन परत प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस की सुरक्षात्मक परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10-50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। यह हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। शोध से पता चला है कि राकेट प्रक्षेपण में वृद्धि होने से ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। हर साल दुनिया भर में सैकड़ों राकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें से कई वाणिज्यिक कंपनियों और राष्ट्र-राज्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। ये लगभग 20 जगहों पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। सभी उत्तरी गोलार्ध में हैं और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रक्षेपण दर अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और रूस से हैं।

पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है कि अधिक राकेट प्रक्षेपण करने से समस्याएं पैदा होने लगेंगी। माना जा रहा है कि एक बार जब दरें प्रति वर्ष दो हजार प्रक्षेपण तक पहुंच जाएंगी, तो ओजोन परत में हो रहा सुधार धीमा पड़ जाएगा। प्रक्षेपण का यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दस गुना ज्यादा है। यह तो स्पष्ट है कि विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रक्षेपण से ओजोन परत पर असर हुआ है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक सौर पराबैंगनी (यूवी) किरणों से बचाती है। पिछली सदी में उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हानिकारक रसायनों के प्रभावों से ओजोन परत में छीजन तेज हो गया था। अब इसमें सुधार है। मांट्रियल प्रोटोकाल के तहत वैश्विक सहकारी समझौतों की बदौलत यह संभव हो सका।

अब राकेट प्रक्षेपण बढ़ने से सुधारों पर पानी फिर रहा है। इस वृद्धि का एक कारण पृथ्वी की कक्षा में कम ऊंचाई पर स्थित हजारों इकाइयों के उपग्रह समूह बनाने की योजना को लेकर चल रहा प्रयास है। इसके लिए कई प्रक्षेपणों की आवश्यकता होती है और यह कई देशों में हो रहा है, जिन्हें कई कंपनियां संचालित कर रही हैं। यह पता लगाने के लिए कि भविष्य में प्रक्षेपण ओजोन परत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने उपयोग में आने वाले राकेट द्वारा उत्सर्जित ओजोन-क्षयकारी रसायनों के ब्योरे जुटाए और राकेट प्रक्षेपण की उच्च दरों के कई परिदृश्यों के तहत वायुमंडलीय संरचना का अनुकरण किया। पाया गया कि हर साल दुनिया भर में लगभग दो हजार प्रक्षेपणों के साथ ओजोन परत तीन फीसद तक पतली हो जाती है। राकेट से निकलने वाले रसायनों के वायुमंडलीय परिवहन के कारण अंटारकटिका में ओजोन को सर्वाधिक नुकसान देखा गया है, भले ही अधिकांश प्रक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में हो रहे हों। अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ने के नतीजे बुरे होने के संकेत हैं। सौभाग्य से, अभी ओजोन का नुकसान कम है। हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। हमें पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले विनाशकारी नुकसान इंतजार नहीं करना चाहिए। जरूरत है कि हम अंधाधुंध होड़ से बचें।

युद्ध के बादल

पश्चिम एशिया में दो धुर-विरोधी देश आमने-सामने हैं। ईरान पर इजराइल के भीषण हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से एक और युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल, इजराइल को लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। जबकि ईरान का दावा है कि यह नागरिक उद्देश्य के लिए है। मगर, बताया जा रहा है कि ईरान ने इस स्तर तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वह अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। इजराइल का दावा है कि इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सचमुच परमाणु बम बनाने में सक्षम हो गया है? बहरहाल, तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया, जाहिर है ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई होनी थी और ऐसा हुआ भी। इससे अब दुनिया में एक और बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इजराइल के हमले में ईरान के तीन शीर्ष सैन्य अधिकारियों सहित कई वैज्ञानिकों की मौत हो गई। यह उसके लिए बड़ा झटका है। दोनों देशों के नेताओं के आक्रामक बयानों से पूरी दुनिया में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं।

ईरान ने कहा है कि इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। उधर, अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है। ईरान से परमाणु समझौते से अलग होने के बाद उसे उम्मीद थी कि वह दबाव में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान उल्टे अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने में जुट गया। ऐसे में अमेरिका के सामने यह चुनौती तो रहेगी कि वह मध्य पूर्व क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों को सुरक्षित कैसे रखे। उधर, इजराइल का इरादा ईरान के परमाणु कार्यक्रम स्थलों को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का है। उन्हीं ठिकानों पर पिछले दिनों उसने हमले भी किए। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इन दोनों देशों से भारत के रिश्ते हैं। ऐसे में भारत की यह सलाह उचित है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए।

पर्यावरण में घुलता प्लास्टिक का जहर

प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया, उत्पादों को सस्ता किया है। लेकिन इस सुविधा की कीमत हम एक ऐसे भविष्य के रूप में चुका रहे हैं, जो प्लास्टिक के कचरे के नीचे दबता जा रहा है। इसके दूरगामी परिणामों पर गंभीरता से विचार करना होगा

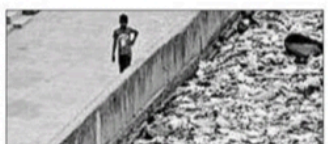

रंजना मिश्रा

प्रदूषण आज दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसा संकट है, जो धीरे-धीरे पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा है। यह प्रदूषण हमारी नदियों, समुद्रों, मिट्टी और यहां तक कि हमारे शरीर में भी प्रवेश कर चुका है। प्लास्टिक, जो कभी सुविधा और टिकाऊपन के कारण एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता था, आज हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। सुबह जब हमारी आंख खुलती है, तो समय पर घंटी बजाने वाली घड़ी से लेकर टूथब्रश, पानी की टंकी से लेकर दूध की थैली तक, हर वस्तु में प्लास्टिक मौजूद है। हमारे भोजन को ताजा रखने वाली पैकिंग, दवाइयों की सुरक्षित बोतलें, बच्चों के रंग-बिरंगे खिलौने, जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरण, संचार के साधन, परिवहन के कलपुर्जे और फैशन की दुनिया, कोई भी क्षेत्र प्लास्टिक के प्रभाव से अछूता नहीं है।

निस्संदेह प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया, उत्पादों को सस्ता किया और कई मायनों में सुरक्षित भी, लेकिन इस सुविधा की कीमत हम एक ऐसे भविष्य के रूप में चुका रहे हैं, जो प्लास्टिक के कचरे के नीचे दबता जा रहा है। इसका उत्पादन इतनी तीव्र गति से और इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है कि हमने इसके अंधाधुंध उपयोग के दूरगामी परिणामों पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया और अब यह हमारे पर्यावरण के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है, जिसका इलाज यदि समय रहते नहीं किया गया तो यह हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य को सदा के लिए नष्ट कर देगा।

वैश्विक स्तर पर हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और अनुमान है कि अब तक उत्पादित कुल प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में हमारे पर्यावरण में मौजूद है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत विकसित देशों की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन हमारी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की कुल मात्रा बहुत अधिक है। नदियां, जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थीं, आज प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों और अन्य कचरे से पटी पड़ी हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां भी इससे अछूती नहीं हैं, जो अपने साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक बहा कर समुद्र तक ले जाती हैं।

हमारे महासागर आज प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार बन चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक, प्रति मिनट एक ट्रक भर प्लास्टिक कचरा समुद्रों में डाला जाता है। यह समुद्री जीवन के लिए मौत का एक जाल है। व्हेल और डाल्फिन जैसे बड़े जीव अक्सर मछली पकड़ने के पुराने जालों में फंस कर दम तोड़ देते हैं। समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ कर निगल लेते हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है और वे भूख से मर जाते हैं। समुद्री पक्षी अपने बच्चों को गलती से प्लास्टिक के छोटे टुकड़े खिला देते हैं, जो उनके पेट में जमा होकर उनकी मृत्यु का

कारण बनते हैं। प्रवाल भित्तियां, जो समुद्री जैव विविधता के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं, वे प्लास्टिक कचरे से ढक कर और दम घुटने से नष्ट हो रही हैं। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री खाद्य शृंखला में प्रवेश कर चुके हैं। छोटे समुद्री जीव प्लवक आदि प्लास्टिक के इन सूक्ष्म कणों

> **प्लास्टिक का प्रदूषण हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह मिट्टी की संरचना को बदल देता है, जल सोखने की उसकी क्षमता को कम करता है और मिट्टी में रहने वाले लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों में बाधा डालता है, इससे कृषि पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस जगह शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है, वह प्लास्टिक से भरी होती हैं। यहां प्लास्टिक कचरे से रिसने वाले जहरीले रसायन भूजल में मिल कर उसे दूषित करते हैं, जिससे जलजनित बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है।**

को खाते हैं, फिर उन्हें छोटी मछलियां खाती हैं और फिर बड़ी मछलियां। जब मनुष्य इन समुद्री जीवों का सेवन करते हैं, तो ये हानिकारक तत्त्व शरीर में भी पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी की संरचना को बदलते हैं, जल सोखने की उसकी क्षमता को कम करते हैं और मिट्टी में रहने वाले लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों में बाधा डालते हैं। इससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है और कृषि पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस जगह शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है, वह प्लास्टिक से भरी होती हैं। यहां प्लास्टिक कचरे से रिसने वाले जहरीले रसायन भुजल में मिल कर उसे दुषित करते हैं, जिससे जलजनित बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। कूड़े के इस अंबार में अक्सर आग लग जाती है। इस दौरान प्लास्टिक जलने पर अत्यंत विषैली गैसें वायुमंडल में फैलती हैं, जो गंभीर श्वसन समस्याओं, त्वचा रोगों और यहां तक कि कैंसर का कारण बन सकती हैं।

इसके अलावा प्लास्टिक कचरे से शहरों की नालियां जाम हो जाती हैं, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आवारा पशु भोजन की तलाश में कूड़े के ढेर में मुंह मारते हैं और खाद्य सामग्री के साथ पालीथिन भी निगल जाते हैं, जो उनकी मौत कारण बनता है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीवों द्वारा प्लास्टिक खाने या उसमें फंसने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हवा में भी माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। जब हम सांस लेते हैं, तो ये कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर अभी शोध जारी है। प्लास्टिक उत्पादन की प्रक्रिया में भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

खाद्य शृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचने वाले माइक्रोप्लास्टिक और उनसे जुड़े रसायन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इनमें हार्मोन संबंधी असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याएं, विकासात्मक विकार, तंत्रिका तंत्र को क्षति और कैंसर का खतरा शामिल है। कुछ अध्ययनों में मानव रक्त और फेफड़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। इस समस्या के मूल में कई जटिल और परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख और स्पष्ट कारण है, एकल-उपयोग प्लास्टिक पर हमारी बढ़ती निर्भरता। पानी की बोतलें, बिस्कुट के रैपर, किराने की थैलियां आदि, ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें हम कुछ मिनटों या घंटों के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। 'इस्तेमाल करो और फेंको' की संस्कृति ने हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता आज बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई है। पर्यावरण केवल पेड़-पौधे, नदी-पहाड़ या जीव-जंतुओं का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। जब हम प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों से इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम संतुलित पर्यावरण की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। यदि हम दृढ़ निश्चय और सामूहिक प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू पा सकते हैं।

रूठे घर की दास्तां

राजेंद्र मोहन शर्मा

दुनिया मेरे आगे

मैं दुनिया को मनाने की खोज में डूबा हूं, और मेरा घर मुझसे रूठता जा रहा है। यह एक ऐसी गहन तड़प है, जो मानव मन की उस जटिल यात्रा को उजागर करती है, जहां मनुष्य बाहरी दुनिया की चमक और घर की आत्मीय छांव के बीच भटकता रह जाता है। यह जीवन की सतह पर तैरती महत्त्वाकांक्षाओं और आत्मा के भीतर गहरे बसे प्रेम, विश्वास और अपनेपन के बीच का द्वंद्व है। मानव जीवन एक संयुक्त धुरी पर टिका है, जहां बाहरी दुनिया की तीव्र लय और घर की मधुर धुन एक साथ गूंजती हैं, पर कभी-कभी एक-दूसरे को खामोश भी कर देती हैं। हम अक्सर दुनिया को जीतने, उसकी तालियां बटोरने और उसकी स्वीकृति पाने की भूख में खो जाते हैं। यह दुनिया एक रंगमंच है, जहां हम अपनी पहचान की ऊंची मीनारें खड़ा करना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि, परिश्रम और छवि को चमकाने में जुट जाते हैं। मगर इस दौड़ में हम अपने घर को भूल जाते हैं। घर वह पवित्र स्थान है, जहां प्रेम की किरणें नृत्य करती हैं, विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं और आत्मीयता की सुगंध हवाओं में तैरती है।

घर का रूठना केवल एक भौतिक स्थान का रूठना नहीं है। यह उस आधारशिला का हिलना है, जो हमें मानवता से जोड़े रखती है। दार्शनिक दृष्टि से यह द्वंद्व मानव जीवन की एक अनिवार्य सैर है। हमारा मन दो ध्रुवों के बीच डोलता है। यह बाहर के अनंत को जीतने की इच्छा और भीतर की जड़ों को थामने की चाह है। घर वह पवित्र सरोवर है, जहां हम बिना किसी मुखौटे के उतर सकते हैं। यह वह आलिंगन है, जो हमारी कमजोरियों को प्रेम में लपेट कर हमें शक्ति देता है। पर जब दुनिया को मनाने में डूब जाते हैं, तो हम इस आलिंगन को ठुकरा देते हैं। हम अपने प्रियजनों की अनकही पुकारों, उनकी मूक नजरों की भाषा को अनदेखा कर देते हैं। धीरे-धीरे, रिश्तों का बगीचा मुरझाने लगता है। जब हम बाहरी दुनिया की दौड़ में शामिल होते हैं, तब अपने 'होने' से विमुख हो जाते हैं। यह दौड़ हमें खोखला करती है, क्योंकि यह हमें अपने घर, मूल और स्वयं से दूर ले जाती है। हम बच्चों की खिलखिलाहट, जीवनसाथी की अनकही पुकार, और माता-पिता की आंखों की मूक भाषा को अनदेखा कर देते हैं। जब हम दुनिया को मनाने में डूबते हैं, हम अपने भीतर की उस पुकार को खामोश कर देते हैं, जो हमें हमारी सच्चाई की और ले जाती है। यह वह स्वर है, जो हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहरी चमक में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। पर हम इस स्वर को व्यस्तता और महत्त्वाकांक्षाओं की धूल में उड़ा देते हैं। क्या इस रूठने का कोई समाधान है? क्या हम दुनिया और घर के बीच सेतु रच सकते हैं? इसका उत्तर आत्म-चिंतन में छिपा है। हमें रुकना होगा, अपने हृदय से सवाल करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या हमारी उपलब्धियां हमें सच्ची तृप्ति दे रही हैं? क्या हमारा घर उतना ही अनमोल नहीं, जितनी हमारी बाहरी दुनिया? हमें अपने घर के लिए गुणात्मक समय निकालना होगा, न केवल भौतिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी।

दुनिया को मनाने और घर को संजोने का कार्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ये एक ही जीवन-संगीत के दो राग हैं। सच्चा आनंद नाद तब जन्म लेता है, जब हम दोनों को एक साथ संतुलन के साथ जीते हैं। जब हम अपनी बाहरी उपलब्धियों को अपनी भीतरी शांति के साथ पिरोते हैं, जब हम अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को अपने प्रियजनों के प्रेम के साथ बांधते हैं, तब जीवन एक काव्य बन जाता है। सच्चा सुख न बाहर की चमक में है, न केवल घर की आत्मीयता में। यह उस संतुलन में है, जहां हम अपनी बाहरी यात्रा को अपनी भीतरी जड़ों के साथ जोड़ते हैं। यह वह साधना है, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है।

> **घर का रूठना केवल एक भौतिक स्थान का रूठना नहीं है। यह उस आधारशिला का हिलना है, जो हमें मानवता से जोड़े रखती है। हमारा मन दो ध्रुवों के बीच डोलता है। यह बाहर के अनंत को जीतने की इच्छा है। घर वह पवित्र सरोवर है, जहां हम बिना किसी मुखौटे के उतर सकते हैं।**

जब हम दुनिया की दौड़ में थक जाते हैं, तो घर वह शरणस्थली है जो हमें प्रेम और विश्वास देती है। पर इसके लिए हमें अपने समय और ऊर्जा को संतुलित करना होगा। हमें सीखना होगा कि बाहरी सफलता की चमक और भीतरी शांति की गहराई एक-दूसरे के पूरक हैं। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए, हमें अपने जीवन को एक तूलिका की तरह देखना होगा, जिससे हम अपने कैनवास पर प्रेम, कर्तव्य और आत्मीयता के रंग भरते हैं। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने, उनकी बातों को सुनने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने का प्रयास करना होगा। यह वह प्रक्रिया है, जो हमें हमारी मानवता से जोड़े रखती है। जब हम अपने घर को समय और प्रेम देते हैं, तो वह रूठना छोड़ देता है। वह फिर से हमारी आत्मा का आलिंगन बन जाता है। इस तरह, जीवन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची पूर्णता बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच संतुलन में निहित है। यह वह कला है, जिसमें हम अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को अपनी जड़ों के साथ जोड़ते हैं, अपनी उपलब्धियों को अपने प्रियजनों के प्रेम के साथ संनादित करते हैं। यह वह साधना है, जो हमें जीवन की गहनता और सुंदरता का अनुभव कराती है।

हादसे पर सवाल

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसे की असल वजह क्या है, यह अभी जांच का विषय है। इसमें कई दिन और महीने तक लग सकते हैं। भारत में हाल में वायुसेना के कुछ विमान एवं निजी कंपनियों के हेलिकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उनमें जनहानि भी हुई है। मगर किसी यात्री विमान हादसे में इतनी अधिक संख्या में लोगों की मौत अरसे बाद हुई है। वर्ष 2010 में मंगलुरु में विमान दुर्घटना में 150 से अधिक लोग मारे गए थे। इससे पहले 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी अरब जा रहे और दिल्ली आ रहे विदेशी एअरलाइन के दो विमान हवा में आपस में टकरा गए थे। अहमदाबाद हादसे का शिकार हुआ विमान ड्रीमलाइनर कंपनी का था। इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। कंपनी के एक इंजीनियर ने जांच के दौरान तकनीकी खामियों की तरफ ध्यान दिलाया था, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया था। यह सवाल गंभीर है कि क्या तब कंपनी ने लीपापोती की थी।

– चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

भावनाओं का दोहन

चुनावी राजनीति में तर्क, नीति और दीर्घकालिक दृष्टि के स्थान पर व्यक्तिपूजा, भावनात्मक ध्रुवीकरण और भीड़ तंत्र का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल जनता की भावनाओं का चतुराई से दोहन कर रहे हैं। चेहरों, नारों और जातीय समीकरणों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तविक मुद्दे गौण हो जाते हैं। विचार और विश्लेषण की जगह भीड़ का मनोविज्ञान हावी हो जाता है। चुनावों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसी प्राथमिकताएं चर्चा से बाहर कर दी जाती हैं। सूचना का बुलबुला, एकतरफा आख्यान और पूर्वाग्रह नागरिकों को सच्चाई से दूर ले जाते हैं। आखिर इस संकट का क्या समाधान है। शिक्षा व्यवस्था में आलोचनात्मक चिंतन, तर्कशीलता और नागरिक शास्त्र का समावेश अनिवार्य है।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

प्रतिकार का समय

अगर अब कभी भी हमारे देश पर कोई आतंकी हमला होता है, तो हम फौरन कार्रवाई करेंगे। फिर चाहे हमलावर पाकिस्तान में जाकर क्यों नहीं छिप कर बैठा हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक साक्षात्कार में कहा है कि हमेशा आतंकी कार्रवाई दुश्मन देश की ओर से ही शुरू की जाती है। ये पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर तनाव का मामला नहीं है, आज आतंक को लेकर भारत की नीति बर्दाश्त न करने की है। आतंकी अगर भारत पर हमला करेंगे, तो हम उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। चाहे इसमें पाकिस्तान भी क्यों न शामिल हो। हम उन आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। देश में कहीं भी किसी भी नागरिक पर आतंकी हमला होगा, तो भारत उसका तुरंत प्रतिकार अवश्य करेगा। विदेश मंत्री इसको लेकर आगाह कह चुके हैं।

– मनमोहन राजावत, शाजापुर

बिखर गए सपने

अहमदाबाद में बोइंग विमान का दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। जाने कितने लोगों के सपने बिखर गए। हादसों के बाद जांच समितियां बनाई जाती हैं, परंतु आए दिन हादसे रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लोग अब कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हादसों के बाद मरने वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी। मगर कुछ दिनों में सब कुछ भुला दिया जाएगा और जीवन सामान्य दिनों की तरह चलने लगेगा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान में जाने कितने सपनों के साथ यात्री उसमें सवार हुए थे। वे सब उनके साथ ही खत्म हो गए और छोड़ गए अपने पीछे रोते-बिलखते परिवार। अब सरकार हादसे की जांच कराई जाएगी। मगर जिन लोगों ने अपनों को इस उड़ान में खोया है वे कभी वापस नहीं आएंगे।

– नरेश कानूनगो 'शोभना', देवास

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com